DADRA AND NAGAR HAVELI BILL

The Deputy Minister of External Affairs) (Shrimati Lakshmi Menon): On behalf of Shri Jawaharlal Nehru, I beg to move for leave to introduce a Bill to make provision for the representation of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli in Parliament and for the administration of that Union territory and for matters connected therewith.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to make provision for the representation of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli in Parliament and for the administration of that Union territory and for matters connected therewith."

The motion was adopted

Shrimati Lakshmi Menon: I introduce the Bill.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक रिक्वैस्ट करनी है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो आज यूरोपियन कौमन मार्केट के ऊपर स्टेटमेंट रखा है उस पर बहस के लिये कम से कम एक दिन का टाईम देना चाहिए। यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि सारे देश की दृष्टि इस तरफ है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन मिनिस्टर साहब से इसका ताल्लुक है उन से बातचीत करके इसका फैसला किया जायगा।

12.18 hrs.

MOTION RE: REPORT OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ENQUIRY COMMITTEE

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up the motion on the report of Aligarh Muslim University Enquiry Committee. Shri Prakash Vir Shastri.

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): The motion stands in the name of four Members and there is also an amendment circulated in the name of 4 other hon. Members. I believe the time allotted is only 2 hours. Are we to take it that no other Members will be permitted to participate in the discussion?

Mr. Deputy-Speaker: As many as can be accommodated will be allowed.

Shrimati Renu Chakravartty: Within the 2 hours?

Mr. Deputy-Speaker: That is the time fixed.

Shri Hem Barua (Gauhati): Would it not be possible to extend the time?

Shrimati Renu Chakravartty: We would request that the names of some Members may be cut out. Some may not want to move the amendment.

Mr. Deputy-Speaker: It is not necessary that everyone of them should be given a chance. Shri Prakash Vir Shastri. He must realise the pressure of time and be as brief as possible. I hope he can finish in 15 minutes.

Shri Prakash Vir Shastri (Gurgaon): Half an hour.

Shri A. M. Tariq (Jammu and Kashmir): This is a very important matter; more time may be allowed.

Mr. Deputy-Speaker: It will not be possible to give him half an hour. He should try to condense his remarks.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के ऐतिहासिक विश्वविद्यालयों में से एक है। २ मार्च सन् १९६० को इसी सदन् में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आधा घंटे की चर्चा उठाई थी। उस चर्चा को उठाते समय मैं ने यहां से इसको आरम्भ किया था कि कोई भी विद्यालय हो अथवा विश्वविद्यालय वह सब ही ज्ञान के

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

मंदिर हैं और इन के सम्बन्ध में जब भी कोई विचार किया जाय, वह धर्म, जाति और दलबंदियों से ऊपर उठ कर होना चाहिए और आज भी मैं इस चर्चा को आरम्भ करते समय उन्हीं भावनाओं को फिर से दुहराना चाहता हूं। मझे यद्यपि दुःख है कि जब पिछली बार मैं ने इस चर्चा को उठाया था तो कुछ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के उर्दू के पत्रों ने और कुछ भारत के कम्यनिस्ट अंग्रेजी पत्रों ने उस चर्चा को उतना पवित्र न रहने दिया फिर भी मैं आशा करूंगा कि जिस पवित्रता के साथ मैं इस चर्चा को आज आरम्भ करना चाहता हूं उस को उसी पवित्र रूप में ग्रहण किया जाय ।

अपनी आध घंटे की चर्जा में मैं ने जिन प्रश्नों को उठाया था उन में विशेष रूप से विश्वविद्यालय में दूषित परीक्षा प्रणाली, छात्रों को प्रवेश देने में पक्षपात, अध्यापकों की नियुक्ति में भेदभाव, अपने अपने सम्बन्धियों की अधिक मात्रा में नियुक्ति, सम्पत्तियों की अनावश्यक खरीद और वित्तीय अनियमितताओं के अतिरिक्त मैं ने यह भी कहा था कि इन तमाम कारणों से विश्वविद्यालय का ढांचा पर्याप्त हिल गया है ।

जांच समिति का गठन जिन आधारों पर हुआ, उस के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा । १ दिसम्बर, १९५९ को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा था कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार की अनियमितताएं कोई नहीं नहीं हैं, वे बहुत समय से चल रही हैं और उन को ठीक करने के लिये समय समय पर यहां से विश्वविद्यालय को निर्देश भी दिये गये, किन्तु उन निर्देशों का उत्तर विश्वविद्यालय की ओर से कोई संतोषजनक नहीं मिला । परिणामस्वरूप विवश हो कर शिक्षा मंत्रालय ने विज़िटर से यह अनरोध किया कि वह अपनी ओर से एक कमेटी एप्वायंट करें । अभी यह चीज़ होने जा ही रही थी कि इस बीच में विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने शिक्षा मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया और, जैसी कि मेरी जानकारी है, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को कहा कि बजाये इस के कि आप विज़िटर्स कमेटी एप्वायंट करें, अच्छा यह हो कि जो सदस्य आप विज़िटर्स कमेटी में रखना चाहते हैं, उन को हम एक्सीक्यूटिव कौंसिल द्वारा एप्वायंट की गई कमेटी में रख देते हैं और वह कमेटी ही विश्वविद्यालय की जांच करे । शिक्षा मंत्रालय उस रहस्यमय सुझाव को उस समय नहीं समझ पाया । लेकिन आगे चल कर इस का भयंकर परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति विश्वविद्यालय एक्ट के हिसाब से उस कमेटी के सदस्य बन गये । उनके सदस्य होने का परिणाम यह हुआ कि जिस व्यक्ति के विपरीत यह सारी जांच होनी थी, जो व्यक्ति दोषी था, वह न सिर्फ़ जूरी का सदस्य था, अपितु अपने बारे में निर्णय देने के लिये न्यायाधीश के रूप में भी बैठा हुआ था । सरकार ने इस सम्बन्ध में उपेक्षा सम्भव है, इस लिये दिखाई कि वह किसी वर्ग-विशेष की भावनाओं को असंतुष्ट नहीं करना चाहती थी । लेकिन साथ ही साथ यह भी प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय में हो रही सब अनियमितताओं के लिये जो मुख्य अपराधी थे—वर्तमान उपकुलपति, उन को भी सरकार बचाना चाहतीं थी । २ मार्च, १९६० को होने वाली आध घंटे की चर्चा में भी मैं ने विशेष रूप से इस बात को कहा था कि यदि इस समिति से निष्पक्ष जांच की आशा करनी है, तो उपकुल प को इस समिति में नहीं बैठना चाहिए । शिक्षा मंत्री जी ने उस समय अपने वक्तव्य में यह कहा था कि मेरा अनुमान है कि वह जांच समिति की बैठकों में भाग नहीं लेंगे और यह समिति उसी प्रकार से काम करेगी, जैसे कि विज़िटर्स कमेटी करती । लेकिन आज मुझे यह कहते हुए और इस सदन को सूचना देते हुए दुःख हो रहा है कि समिति की जिन

मीटिंगों में विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कर्मचारी और विश्वविद्यालय के नागरिक उपस्थित हुए, उन सब में ही उपकुलपति बराबर मौजूद रहे । भय और खौफ़ के वातावरण में, जो आज भी मुस्लिम विश्वविद्यालय में बना हुआ है, विश्वविद्यालय के किसी भी सदस्य के लिये यह असम्भव था कि वह जांच समिति के सामने उपकुलपति के विरुद्ध कोई शब्द जा कर कहे । उपकुलपति ने सही जांच न होने देने के लिये जो प्रक्रिया अपनाई, वह बहुत ज्यादा खेदजनक थी । जैसा कि मैं ने कहा है, सब से पहले उन्होंने मंत्रालय से मिल कर विजिटर्ज़ कमेटी के बजाये एक्सीक्यूटिव कमेटी की ओर से कमेटी बनवाई, लेकिन दूसरा काम उन्होंने यह किया कि जो करार इस समिति के सम्बन्ध में हुआ था, आगे चल कर उन्होंने उस करार को भी तोड़ा और उस कमेटी में दो व्यक्ति और आगे चल कर रहस्यमय ढंग से सम्मिलित किये गये । उन व्यक्तियों में एक थे विश्वविद्यालय की कोर्ट के सक्रिय सदस्य, श्री पी० एन० सपरू और दूसरे काश्मीर के रिटायर्ड जज, श्री शाहमीरी थे । उन दोनों व्यक्तियों के सम्मिलित होने से उपकुलपति को अपने लिये सहयोग प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिली । उदाहरणस्वरूप मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर यह चर्चा की है कि उपकुलपति ने आवश्यकता न होते हुए भी १३५ बार अपनी आपात्कालीन शक्तियों का उपयोग किया और उस में ५२ बार इस प्रकार के थे कि जिन में उन को आपात्कालीन शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए था । समिति तो यह राय दे रही है, लेकिन जो दो व्यक्ति मध्य में सम्मिलित किये गये थे, उन्होंने समिति की राय से असहमति प्रकट की है और इस विषय में अपना एक विशेष नोट जोड़ा है । इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकार रहस्यमय ढंग से जो दो व्यक्तियों को बीच में सम्मिलित किया गया, उस के पीछे कौनसी भावना छिपी हुई थी ।

इसके अतिरिक्त एक और बात है । बनारस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जब इस प्रकार की कमेटी नियुक्त हुई, तो उस ने पहला काम यह किया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को परिपत्र जारी किया और एक प्रश्नावली भेजी गई । मुथम कमेटी ने भी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नियुक्त की गई थी, सब से पहले यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हम को कुछ जानकारी देने के लिये आयेंगे, हम उन को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी । परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जांच समिति की ओर से इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया और न ही इस प्रकार की कोई प्रश्नावली भेजी गई, न परिपत्र ही जारी किये गये ।

इस सम्बन्ध में सब से अधिक आश्चर्य की बात और एक यह है कि भारत सरकार को बदनाम करने के लिये इस प्रकार की सुनियोजित प्रचार-योजना चलाई गई कि भारत सरकार मुस्लिम विश्वविद्यालय को फूटी आंख नहीं देखना चाहती, वहां इस प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए है, जो मुस्लिम विश्वविद्यालय को समाप्त करना चाहते हैं । समाचारपत्रों के द्वारा भी इस प्रकार का प्रचार किया गया और भाषणों के द्वारा भी । इस का परिणाम स्वाभाविक था कि साम्प्रदायिक घृणा फैलती । उपकुलपति के भय से सारे वातावरण में यह समाचार फैला हुआ था कि जो भी व्यक्ति उपकुलपति के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे तुरन्त हटा दिया जायगा । ये बातें केवल अफ़वाह ही नहीं थीं । मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं कि आगे चल कर इस प्रकार की घटनायें घटीं कि जिन लोगों ने

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

समिति के सामने गवाही दी, उन में कुछ व्यक्तियों को प्रतिष्ठा की हानि उठानी पड़ी, कुछ व्यक्तियों को शारीरिक आघात सहना पड़ा, कुछ व्यक्ति बुरी तरह डराये धमकाये गये और कुछ व्यक्तियों को अपने स्थानों से हटा दिया गया ।

इस सदन में पहले भी इस प्रकार की चर्चा आई थी कि इंजीनियरिंग कालेज के तत्कालीन प्रिंसिपल, प्रोफ़ेसर साहा, को वाइस-चांसलर के मकान के पास पीटा गया । मंत्रालय को इस सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट की यदि जानकारी होगी, तो मालूम होगा कि इस पीटने में उपकुलपति के मकान में रहने वाले कुछ कर्मचारी सम्मिलित थे ।

इसी प्रकार गणित विभाग के एक बहुत अच्छे अध्यापक, डा० रस्तोगी, को विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समिति को खुले रूप से ज्ञापन दिया था । लेकिन ऐसा योग्य अध्यापक, जिस को अलीगढ़ विश्वविद्यालय न खपा सका, आज अमरीका के ओहियो विश्वविद्यालय में गणित का अध्यापक हो कर पहुंच गया है । मैं आप की जानकारी के लिये यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे पता लगा है—और अधिक शिक्षा मंत्री जी पता लगायें—कि वर्तमान उपकुलपति ने न केवल उनको अलीगढ़ विश्वविद्यालय छोड़ने पर विवश किया, बल्कि अब जिस विश्वविद्यालय में वह इस समय सर्विस कर रहे हैं, उस को भी उन्होंने अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय देते हुए उनके खिलाफ़ कुछ पत्र लिखे हैं ।

इसी प्रकार डा० जैमन को भी, जो इंजीनियरिंग कालेज में नियुक्त थे, वेतन के सम्बन्ध में परेशान किया गया ।

उपकुलपति और उन दो व्यक्तियों की उपस्थिति का, जो कि बीच में रहस्यमय ढंग से सम्मिलित किये गये थे, परिणाम यह हुआ कि शिक्षा मंत्री जी का वह सारा उद्देश्य समाप्त हो गया जिसे उन्होंने कहा था कि यह कमेटी विज़िटर्ज़ कमेटी की तरह से काम करेगी । जो कार्य-प्रणाली पहली कमेटी निर्धारित करती, वह भी अचंभा बदल गई । लेकिन एक विशेष बात में यह कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं समझ पाया कि शिक्षा मंत्री जी ने जब इस सदन में प्रश्नों का उत्तर देते हुए और वक्तव्य देते हुए कई बार यह संकेत दिया था कि उपकुलपति इस समिति में नहीं बैठेंगे, तो फिर वह क्यों डटे हुए थे कि वह समिति की बैठकों में भाग लेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में जांच समिति के प्रतिवेदन मे गम्भीर त्रुटियों का आ जाना स्वाभाविक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । प्रतिवेदन में उपकुलपति के खिलाफ़ लगाये गये विभिन्न आरोपों की न तो पुष्टि की गई है और न ही उन का खंडन किया गया है । जांच समिति ने इस विषय में जो मौन साधा है, समझ में नहीं आता कि उस का क्या अर्थ लगाया जाये । जांच समिति की रिपोर्ट में भी कहीं स्पष्ट भाषा में और कहीं दबी हुई भाषा में विचार प्रकट किये गये हैं और कहीं विचारों का बिल्कुल लोप ही कर दिया गया है—सरस्वती के प्रवाह की तरह समिति कहीं प्रकट होकर चली जाती है और कहीं पाताल में चली गयी है । इस प्रकार यह जांच समिति एक पहेली बन कर रह गई है । उस को स्पष्ट भाषा में निर्देश देने चाहिए थे, लेकिन वह नहीं दे पाई । समिति ने काफ़ी नम्र भाषा का भी यद्यपि प्रयोग किया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि मक्खी को तो कोई निगल सकता था, किन्तु हाथी को कोई कैसे निगल सकता था ? बुराइयां इतनी अधिक थीं कि समिति अगर उन को दबाने का प्रयत्न भी करती, तो भी उस में सफल न होती । परिणाम यह हुआ है कि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था की बुराइयों की छान-बीन करने के पश्चात् भाई-भतीजावाद को संरक्षण, अनाचार, सार्वजनिक धन के गबन एवं दुरुपयोग के मामले समिति ने प्रकाश में लाये । हमारे देश के

विश्वविद्यालयों के इतिहास में यह एक भयंकर घटना है कि किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार से भयंकर रूप में धन का और अधिकारी का दुरुपयोग हुआ हो ।

मैंने आधे घंटे की चर्चा में उदाहरण दिया था कि मेडिकल कालेज के लिये पचास लाख रुपये की राशि दी गई थी । केन्द्रीय सरकार की ओर से जो फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पर गये, उन्होंने कहा कि जो राशि मेडिकल कालेज के लिये दी गई थी, उसका प्रयोग उस में न कर के दूसरे रूप में किया गया । लेकिन समिति ने इस से एक कदम आगे जाकर एक और रहस्योद्घाटन किया है । उसने रिपोर्ट के पृष्ठ २८, पैरा ७ में यह लिखा है कि जब हम आडिट के लिये गये, तो आडिट के समय दान का रजिस्टर हम को नहीं दिखाया गया, जिस से यह पता लग सकता कि कितनी और अन्य राशियां प्राप्त की गई । ऐसा प्रतीत होता है कि नवम्बर १९४४ के बाद एक अलग कैश-बुक बनाई गई, परन्तु पहली कैश-बुक लापता है, जिस में १९४५ तक का लेन-देन दर्ज था । १,२९,४७५ रुपये की राशि मेडिकल कालेज फंड में जमा नहीं की गई और न ही इकट्ठा करने वाली एजेन्सी के संतुलन-पत्र में इस का उल्लेख है । जब कोषाध्यक्ष से समिति ने इस सम्बन्ध में पूछा तो कोषाध्यक्ष ने उत्तर दिया कि अभी जांच चल रही है लेकिन समिति ने इसको बड़ी निर्भीकता के साथ प्रकट किया है । उसने लिखा है कि असल भुगतान के बाद विश्वविद्यालय के रिकार्डों में हेरफेर भी किये गये है । आप अनुमान लगाइये कि जिस विश्वविद्यालय को केन्द्र से लाखों नहीं करोड़ों रुपया मिलता है वहां इस तरह की चीजें होती हैं । न केवल यह बल्कि समिति ने इससे भी ज्यादा बड़े भारी एक रहस्य का भण्डाफोड़ किया है। समिति ने लिखा है कि जांच समिति की नियुक्ति से पहले १३ लाख रुपया इस प्रकार का था विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जिस का कोई हिसाब किताब नहीं था या जिस के हिसाब किताब का कुछ पता नहीं था ।

इन सभी चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए इस जांच समिति की नियुक्ति की गई थी । जैसा मैंने पहले आध घंटे की चर्चा शुरू करते हुए कहा था बहुत से आदमी इस प्रकार के थे कि जिनके नाम पर लिखे विश्वविद्यालय के रुपये बट्टे खाते में डाल दिये गये । समिति ने स्वयं इस प्रकार के उदाहरण दे कर मेरे इस कथन की पुष्टि की है । एक व्यक्ति जिसके नाम पर ७८,००० रुपया था, आप अनुमान लगाइये कि सौ दो सौ नहीं, ७८,००० रुपया था, विश्वविद्यालय ने यह कहकर उसे बट्टे खाते में डाल दिया कि वह व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है, लिहाजा यह रुपया वसूल नहीं किया जा सकता है । सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी वह व्यक्ति कानपुर है और यू०पी० गवर्नमेंट से पेंशन हासिल कर रहा है जबकि मैं अपनी यह बात कह रहा हूं । यह उस विश्वविद्यालय की स्थिति है । जैसा जांच समिति ने कहा है मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ कदम उठायें । जांच समिति ने बड़ी निर्भीकता के साथ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उपकुलपति ने १३५ बार १९५५ से १९६० की अवधि में अपनी आपत्कालीन शक्तियों का प्रयोग किया है । समिति की राय है कि इनमें से कम से कम ५२ मामले ऐसे थे, जिनमें आपत्कालीन शक्तियों का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इससे साफ प्रतीत होता है कि उपकुलपति के कुछ इस प्रकार के प्रिय-पात्र थे या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति थे जिन के लिए उन्होंने एग्जेक्टिव काउंसिल के निर्णयों की प्रतीक्षा नहीं की और ५२ बार अपनी आपत्कालीन शक्तियों का प्रयोग किया । आश्चर्य की बात है कि आज के हिन्दुस्तान में भी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के ८ व्यक्ति उपकुलपति हैं जो इतनी अधिक बार आवश्यक न होते हुए भी अपनी आपत्कालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं । ऐसे व्यक्ति को तो अविलम्ब हटाया जाये ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी लिखा है कि जब जब सरकार ने उनको इण्टरनल आडिट के लिए कुछ इस प्रकार का सुझाव दिया या आडिट के सम्बन्ध में कुछ और भी संकेत दिए तो विश्वविद्यालय बराबर उनकी उपेक्षा करता गया ? एक इण्टरनल आडिटर जब रखा भी गया तो किस व्यक्ति को रखा गया । रामपुर से एक व्यक्ति को मंगा कर इण्टरनल आडिटर रख लिया गया जहां पर कि उपकुलपति महोदय के महत्वपूर्ण कुछ वर्ष व्यतीत हुए हैं । उसको १९५६ से १९५८ तक विश्वविद्यालय के आडिट के काम पर लगाया गया ।

समिति ने, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी लिखा है कि जब हमने भवन निर्माण के सम्बन्ध में कारिन्दों से पूछा कि क्या आपके पास कोई हिसाब किताब है तो समिति ने कहा है कि कारिन्दों ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है । ये सब वित्तीय अनियमिततायें हैं, जिनकी ओर मैं चाहता हूं सदन ध्यान दे ।

समिति ने एक और बहुत बड़ी बात लिखी है । उसने लिखा है कि १९४७–४८ के बाद से विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में ढाई गुना की वृद्धि हुई है परन्तु उसी अवधि में विश्वविद्यालय का आवर्तक व्यय चार गुना बढ़ गया है । यह पता नहीं चला कि इसमें इतनी अधिक वृद्धि कैसे हो गई है । केन्द्र विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपया देता है जिसका कोई हिसाब किताब ही विधिवत् वहां नहीं है ।

समिति ने तिबिया कालेज के सम्बन्ध में भी कुछ अपनी कलम चलाई है । तिबिया कालेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन की यह घटना है । मेरे पास कुछ फोटो स्टेट कापियां हैं और उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने बच्चों के नम्बर बढ़वाने के लिए लिखी हैं । ये उनके अपने हाथ की लिखी हुई हैं । दवायें जिनके बारे में यह तथ्य है कि ६५ रुपये की भेजी गयीं हैं, पार्सल के ऊपर लिख दिया गया कि दो सौ रुपये की हैं और जब पैसा आया तो विश्वविद्यालय के दवाखाने में तो ६५ रुपये जमा करा दिए गए और बाकी जो पैसे थे वे प्रिंसिपल साहब की जेब में चले गए । यह सब होने के बावजूद भी आप अनुमान लगायें कि जब उनकी उम्र ६० वर्ष हो गई और उनके रिटायरमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र तो चांद के हिसाब से चलती है और हर ३६ साल के बाद एक साल कम हो जाता है, इसलिए मेरे दो साल बाकी हैं । अब स्थिति यह आकर बनी है कि जब उनकी उम्र साठ साल हो गई है तो उपकुलपति महोदय उनको एक्सटेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं । यह उस विश्वविद्यालय की बात है । समिति ने आखिर में जाकर एक बात इस प्रकार की लिखी है कि मैं समझता हूं कि अगर केवल इन्हीं तीन लाइनों को लेकर यह हाउस कोई निर्णय लेना चाहे तो बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है ।

समिति ने पृष्ठ ३३ पर यह भी स्वीकार किया है कि विभाजन के बाद उत्पन्न नई परिस्थितियों में यूनिवर्सिटी के कर्मचारी और जिम्मेदार लोगों ने भी वैयक्तिक लाभ कमाने की कोशिशें कीं और उस कोशिश यूनिवर्सिटी में हिसाब किताब की ठीक व्यवस्था न रहने के कारण खूब कामयाब रही । खूब लूट वहां चली, उसके बारे में कमेटी भी यह कहती है कि वह खूब कामयाब रही और यह तभी सम्भव हुआ क्योंकि वहां हिसाब किताब की कोई व्यवस्था न थी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय हो उसके द्वारा किसी भी छात्र के लिये बन्द नहीं होने चाहिये । लेकिन इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार की स्थिति नहीं है । पुरानी बातों को तो आप छोड़िये । कमेटी ने जो कहा है मैं वही कहता हूं । उसने जिस समय विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पूछा कि हमें

रिकार्ड बताइये कि विश्वविद्यालय में भरती किस आधार पर की गई है और किस साल में कितने लड़के भरती किए गए हैं और कितनों ने आवेदनपत्र दिये थे, उनमें से कितने फर्स्ट कितने सैकिंड डिवीजन्ज के थे, तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिये कोई रिकार्ड ही पेश नहीं किए गए । ऐसी स्थिति में समिति ने यह लिख दिया कि इस सम्बन्ध में वह जानकारी लेना चाहती थी लेकिन जब रिकार्ड ही नहीं मिल पाए तो कैसे जानकारी ली जा सकती थी ।

१९६१ का इंजीनियरिंग कालेज का रिकार्ड मैं शिक्षा मन्त्री महोदय को बतलाना चाहता हूं । इस बार इंजीनियरिंग कालेज में जो भर्ती हुई है उसमें बाहर से डेढ़ सौ विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र भेजे थे । इनमें सवा सौ हिन्दू विद्यार्थी थे और २५ मुसलमान । इन १२५ हिन्दू विद्यार्थियों में से ४० विद्यार्थी लिए गए यानी ३३ परसेंट । उनको दाखिल किया गया और २५ मुसलमान लड़कों में से १७ लिये गए । इन सब की डिवीजनों आदि का पता लगायें और यह देखें कि किस आधार पर यह भर्ती की गई है तो मेरे कथन की स्वयं पुष्टि हो जाएगी कि भारी अनियमिततायें बरती गई हैं । कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कि पहले से यहां पर पढ़ते चले आ रहे हैं । इस तरह के ६२ विद्यार्थी थे । इन ६२ में से ४२ मुसलमान और २० हिन्दू विद्यार्थी लिए गए । मैं कहना चाहता हूं कि अगर रिजर्वेशन ही आप यहां पर रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं कानून बना कर इसको रख लेते हैं और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय के द्वार हर एक के लिए खुले होने चाहियें और जो स्थिति वहां अब है उसका अन्त होना चाहिये । योग्यतानुसार प्रवेश हो ।

किसी भी विश्वविद्यालय का शिक्षा सम्बन्धी स्तर यदि मापना हो तो उसका एक स्पष्ट माप-दण्ड शिक्षा परीक्षा प्रणाली होती है । पहले भी आध घंटे की चर्चा शुरू करते हुए मैंने कई उदाहरण दिए थे । उस समय मैं ने कहा था कि इनके बारे में और जानकारी अगर आप लेना चाहें तो मैं दे सकता हूं । समिति ने भी इस बारे में जानकारी लेनी चाही थी लेकिन वह उसको नहीं दी गई और ऐसी हालत में समिति अपना क्या विचार प्रकट कर सकती थी और अपनी क्या सम्मति दे सकती थी । इसको आप छोड़िये । मेरे पास कुछ उदाहरण हैं । एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं । उससे सारी स्थिति साफ हो जाएगी । तिबिया कालेज का प्रासपैक्टस मेरे पास है । मेरे पास मार्कशीट भी ओरिजनल हैं । इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी छात्र को कम्पार्टमेंट तब दिया जाएगा जब वह २५ परसेंट नम्बर प्राप्त कर लेगा । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, ओरिजिनल मार्कशीट है, इसमें लिखा हुआ है कि पांच पांच नम्बर वालों को या पांच पांच परसेंट नम्बर वालों को कम्पार्टमेंट दिया गया है और किसी के ३३ परसेंट नम्बर भी हैं, तो उसको कम्पार्टमेंट नहीं दिया जा रहा है ।

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): The hon. Member is quoting from some documents and letters. Would he be pleased to place them on the Table of the House?

Mr. Deputy-Speaker: Yes, if it is desired.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां, मैं सब पेश कर सकूंगा । आप इनसे खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि वहां क्या हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात और है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसको मैं गौर से सुन रहा हूं । हम आज इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं । इसमें अब अगर और नई बातें लाई जायेंगी तो मुश्किल हो जाएगी । उस सूरत में क्या एक और कमेटी मुकर्रर की जाएगी ? आपने जब सवाल उठाया था और जो बातें उसमें उठाई थीं उनकी जांच करने के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, वह हमारे सामने है । उसके आधार पर आपको जो कुछ कहना हो कहें, आपको इसका हक है। मगर जब नई बातें आप लायेंगे, तो

[उपाध्यक्ष महोदय]

मुश्किल हो जाएगी और वह ठीक भी नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं ये नई बातें नहीं पेश कर रहा हूं। इसी से सम्बन्धित बातें मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कमेटी जिस उद्देश्य से स्थापित की गई थी, वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, उसका इस प्रकार का वातावरण ही नहीं रहने दिया गया जिसमें वह खुल कर काम कर पाती।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपने कह दिया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह अत्यन्त आवश्यक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राष्ट्रपति की कमेटी एप्वाइंट की जाए तब विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में पूरी जानकारी मिल सकेगी। मैं यह जो जानकारी दे रहा हूं, यह इसी से सम्बन्धित दे रहा हूं।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : आप क्या कमेटी के सामने पेश हुए थे और ये तमाम केसिस क्या आपने कमेटी के सामने पेश किए थे ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां, मैं खुद कमेटी के सामने पेश हुआ था और जो कुछ भी मैं उसके सामने पेश कर सकता था किया था लेकिन मुझे दुःख है कि उनमें से बहुत सी बातों को कमेटी ने इसके अन्दर नहीं रखा और अब मैं आ रहा हूं उन ही बातों पर। मैं आपको स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं कि हाउस में तो मैं लांछन लगाऊं लेकिन बाहर जाकर कुछ और ही कहूं। इस प्रकार के व्यक्ति और होंगे जो पूंछ दबा कर भाग जायें। जो लांछन हैं, वह हाउस में और बाहर भी समान रूप से लगाये जाने चाहियें। जो बात हाउस के के लिए सच है, वह बाहर भी सच है।

अब मैं नियुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इनका जांच-समिति ने अपनी रिपोर्ट में सातवें अध्याय में उल्लेख किया है। मैंने पीछे सदन में इस प्रकार की चर्चा उठायी थी कि किस प्रकार योग्य से योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी, जिनकी उपाधियां आदि ज्यादा अच्छी थीं, दूसरे व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयी और उन अधिक व्यक्तियों की उपेक्षा कर दी गयी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जांच समिति ने उन अनियमित नियुक्तियों के बड़े बड़े मामलों का जिक्र तक भी नहीं किया। मैं आपसे यह बात इस दृष्टि से कह रहा हूं कि आप इन तमाम चीजों को देखें। वहां हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैड नूरुल हसन साहब की नियुक्ति किस प्रकार से की गयी। आप इसको इस प्रकार की नियुक्तियों का एक उदाहरण समझ लीजिए। डा० नूरुल हसन इससे पहले लखनऊ में लेक्चरार थे। जब उनके स्वशुर अलीगढ़ यूनिवरसिटी के वाइस चांसलर थे तो वे वहां रीडर नियुक्त किए गए। बाद में उनको ऐसे ढंग से प्रोफेसर बनाया गया कि इतिहास विभाग को बिना पूछे एक पद बना दिया गया, नियुक्ति चुनाव समिति के बिना ही की गयी और ऐकेडेमिक काउंसिल के बिना पूछे ही उनको इतिहास विभाग में कनफर्म कर दिया गया। यह सब कुछ विश्वविद्यालय एक्ट के विपरीत किया गया क्योंकि उपकुलपति महोदय और नवाब रामपुर के पुराने सम्बन्ध थे और इसलिए उनको उन्हें संरक्षण देना था। इसी तरह से प्रोफेसर सरूर की एप्वाइंटमेंट हुई और इसी तरह डा० अलीम की एप्वाइंटमेंट हुई।

मैंने पीछे दूसरी चर्चा में आपको इस प्रकार का उदाहरण दिया था कि इस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ऐसे थे जिनको पक्षाघात यानी लकवा लग गया था और जो न पूरी तरह से चल सकते थे और न पूरी तरह से बोल सकते थे। विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने मेरे वक्तव्य के विपरीत एक वक्तव्य समाचारपत्रों में प्रकाशित कराया, लेकिन मुझे खुशी है कि जांच समिति ने उसकी जांच की और मेरे कथन को सत्य पाया।

मैं आपको संक्षेप में अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाने से पहले यह कहना

चाहता हूं कि जांच समिति की बैठकों में उपकुलपति क्यों बैठे । आखिर इसमें रहस्य क्या था ? रहस्य यह था कि वह चाहते थे कि उनकी उपस्थिति में लोग स्वतन्त्र होकर समिति के सामने बात न कह सकें जो कि उनके विरुद्ध जाए या इसका यह भी एक कारण था कि वह समझते थे कि इस प्रकार मौजूद रहने से वे समिति के सदस्यों को अपने पक्ष में कर सकेंगे । और जो लोग इस विश्वविद्यालय से परिचित हैं वह जानते हैं वह इन दोनों कार्यों में वह सफल भी हुए । उनकी उपस्थिति से पूरी सूचना भी समिति को प्राप्त हो सकी और समिति ने कई मामलों में या तो नरमी से काम लिया या फिर उनको बिल्कुल ही टाल दिया । समिति से निकट सम्पर्क में होने से उनको इस बात का भी अवसर मिल गया कि जांच के समय वह विश्वविद्यालय के पूरे प्रशासन पर अधिकार रख सके । उनकी इच्छा के अनुसार सामग्री एकत्रित की गयी और छांटी गयी । यह कहने से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मैं समिति की नीयत पर हमला करूं लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समिति में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने जांच समिति के सत्य तक पहुंचने के मार्ग में बाधा डाली । समिति के साथ उपकुलपति के बैठने का दुष्परिणाम यह हुआ कि जो गलत नियुक्तियां हुई थीं जैसे कि डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो कि उपकुलपति के भतीजे हैं, जिसके बारे में परिशिष्ट में बतलाया गया है, उनके बारे में, चूंकि उपकुलपति वहां पर थे, इसलिये जांच समिति ने यह तो लिख दिया कि उनकी जो नियुक्ति हुई वह ठीक नहीं हुई, लेकिन जांच समिति ने मजबूत भाषा में कोई सिफारिश नहीं की । इसका कारण यह था कि उपकुलपति बगल में बैठे थे लिहाजा वह ऐसा नहीं लिख सकते थे । ऐसा ही लगभग इतिहास विभाग के कुछ प्रोफेसरों के सम्बन्ध में है ।

मैंने कमेटी को एक बात विशेष रूप से कही थी कि मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अगर यह कमेटी स्वतन्त्र रूप में निर्णय लेना चाहती है तो दो चार बैठकें ऐसी जरूर होनी चाहिए जिनमें विश्वविद्यालय के उपकुलपति मौजूद न हों । मैंने स्वयं उपस्थित होकर समिति को यह बात कही थी । लेकिन विश्वविद्यालय के उपकुलपति को यह डर था कि जब तक वह बैठे रहेंगे तभी तक वह बातें छिपी रहेंगी, उनके न रहने से वे तमाम बातें सामने आ जाएंगी । मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उपकुलपति की उपस्थिति से क्या नुकसान हुआ । एक व्यक्ति थे जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो ट्रांसमिटर था उसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी थी और उसके लिए उन्होंने एक बड़े आई० ई० एस० आफिसर की, जो कि इंजीनियरिंग कालिज के प्रिंसिपल थे, एक चिट्ठी भी पेश की थी । लेकिन चूंकि उपकुलपति मौजूद थे उन्होंने वापस जाकर उनसे जवाब तलब किया कि यूनीवरसिटी की इनफारमेशन आपने दूसरे व्यक्ति को क्यों दी । उन्होंने उस व्यक्ति को चिट्ठी लिखी । मेरे पास वह ओरिजिनल लैटर मौजूद है और अगर आप चाहें तो मैं उस को पेश कर सकता हूं । उपकुलपति के समिति में बैठने से यह नुकसान हुआ कि समिति के सामने तो वे गवाहियां लेते थे और वापस आकर जवाब तलब करते थे । आप बतलाइए ऐसी स्थिति में जांच समिति कैसे किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुंच सकती थी । मेरे पास डा० चाकों की चिट्ठी है जिनसे इस प्रकार जाकर पूछा गया ।

एक बात और है जिसको दुःख के साथ कहना पड़ता है कि समिति ने यह तो कहा कि आपत्कालीन शक्तियों का वाइस चांसलर ने दुरुपयोग किया, लेकिन उसके साथ साथ यह सुझाव रख दिया कि प्रो वाइस चांसलर का पद खत्म कर दिया जाए । । मैं नहीं समझ पाया कि यह बात कैसे रख दी गयी । प्रो वाइस चांसलर की ही तो एक थोड़ी सी रोक थी इसको भी हटाने का सुझाव कैसे दिया गया । इसमें कहा गया है कि उसके

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

स्थान पर एक रेक्टर बना दिया जाए । रेक्टर तो वाइस चांसलर का हैडक्लर्क हो सकता है । रेक्टर प्रो वाइस चांसलर का काम कैसे कर सकता है । यूरोप के जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं सब में प्रो वाइस चांसलर हैं, बनारस विश्वविद्यालय में है और कई दूसरे विश्वविद्यालयों में है । यह प्रो वाइसचांसलर खत्म करने की बात क्यों की गयी । इसका कारण यह है कि समिति को वाइस चांसलर द्वारा आपत्कालीन शक्तियों का दुरुपयोग का पता लगा । प्रो वाइस चांसलर वाइस चांसलर को बिल्कुल निरंकुश होकर कार्य नहीं करने देता था । इसलिये उन्होंने समिति पर इस प्रकार का प्रभाव डाला कि समिति यह सुझाव दे कि प्रो वाइस चांसलर का पद ही समाप्त कर दिया जाए । मैं तो समझता हूं कि आज इस सदन को दृढ़तापूर्वक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जिन विश्वविद्यालयों में प्रो वाइस चांसलर नहीं हैं उनमें भी प्रो वाइसचांसलर रखे जाएं ।

जांच समिति ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें रिश्तेदारियों की चर्चा भी की है । सदन को यह जानकर हैरानी होगी । इतने रिश्तेदारों की इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति से लगता है कि यह एक राष्ट्रीय सम्पत्ति न होकर पारिवारिक सम्पत्ति बनती चली जा रही है । आप इसकी रिपोर्ट को पढ़ कर देखें, इसमें लिखा है कि वाइसचांसलर के १९ रिश्तेदार विश्वविद्यालय में हैं, डाक्टर अलीम के २०, प्रोफेसर महमूद हुसैन के ९ और प्रोफेसर सरूर के ८ रिश्तेदार हैं । इस प्रकार से तो यह एक घर घर की यूनीवरसिटी होती चली जा रही है ।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाने से पहले उपाध्यक्ष जी, आप से यह चाहूंगा कि इस विषय में मैं ने बहुत कुछ जानने का प्रयत्न किया है, इसलिए मुझे अपनी बात कहने के लिए पांच सात मिनट का समय और दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने २६ मिनट पहले ही ले लिए हैं । दो तीन मिनट में खत्म कीजिए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैंने इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह कहा था कि कुछ अनावश्यक सम्पत्ति की खरीद की गयी और इस अनावश्यक सम्पत्ति की खरीद के सम्बन्ध में मैंने एक बहुत बड़ी जमीन की भी चर्चा की थी, आज फिर मैं उस बात को दुहरा देना चाहता हूं । पता नहीं क्यों समिति ने इस चीज को टालने का प्रयास किया । जहां तक इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से यह जमीन खरीदने का मामला है मेरे पास उसका नक्शा है । बहुत से सदस्य वहां पर जाकर नहीं देख सकते । आप देखिए कि एक तो जिस वक्त विश्वविद्यालय ने यह जमीन खरीदी उस समय उस मद में पैसा नहीं था, दूसरी मद में से पैसा लेकर इस पर लगाया गया । लेकिन अगर इस जमीन की इतनी जरूरत थी तो सन् १९५७ से सन् १९६१ तक यह जमीन क्यों खाली पड़ी हुई है और इसमें चरी और बाजरा क्यों बोया जा रहा है । दूसरे आप एक चीज और देखिए कि जो जमीन को बेचने वाले हैं वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बैठे हैं । यानी बेचने वाले भी वही हैं और खरीदने वाले भी वही हैं ।

तीसरी एक चीज और है । एक व्यक्ति को भी यह देखने को कहा गया कि इसका दाम ठीक है या नहीं । उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस जमीन का दाम ठीक दिया गया है । मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी बात की जांच करने के लिए एक आदमी की नहीं बल्कि तीन आदमियों की कमेटी बनानी चाहिये थी । आप देखें कि इस जमीन के पीछे ही गवर्नमेंट प्रेस की जमीन है जो कि ३५ नये पैसे गज जाती है और इस जमीन का दाम ३ रुपया प्रति वर्ग गज दिया गया है । उसी के बगल वाली एक और जमीन १७ नये पैसे गज में बिकती है । उन जमीनों के दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं जिनको आप चाहें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं । आप

अन्दाजा लगाइए कि इतनी बड़ी जमीन के के सम्बन्ध में एक आदमी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय कर लिया गया और कह दिया गया कि ऐसी कोई चीज नहीं की गयी ।

इसी तरह से मैंने एक मकान की चर्चा की थी जो सैयदेन साहब का मकान था । उसके सम्बन्ध में कमेटी ने लिखा है कि ठीक पैसा दिया गया । हो सकता है कि ठीक पैसा दिया गया हो । वाइसचांसलर साहब कहते हैं कि प्लिन्थ एरिया इतना था । गांव के मकानों के प्लिन्थ एरिया इससे भी ज्यादा होते हैं । लेकिन एक रहस्यपूर्ण बात और है । विश्वविद्यालय की कौंसिल ने अपना १७-१८ नवम्बर का जो रिजोल्यूशन पास किया उसमें कहा कि इस मकान की कीमत ३१,२२९ रुपए है और इसमें हैंड पम्प और इलेक्ट्रिक फैन भी शामिल है । लेकिन इसके बाद उस भूमि पर जो पेड़ खड़े हुए थे उनके लिए भी उनको ६५९ रुपए के करीब दिए गए । यह जमीन तो यूनिवरसिटी की थी तो फिर उसके पेड़ों के पैसे क्यों दिए गए ।

अन्त में मैं यह बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा । मैं यह बात इसलिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि कमेटी ने इस पर सरसरी नजर डाली है । यह विश्वविद्यालय एक विशेष राजनीतिक पार्टी का अड्डा बनता चला जा रहा है । यहां के कितने ही विभाग इस तरह के हैं । हिस्ट्री विभाग, पालिटिक्स विभाग, जागरफी विभाग, इस्लामी शिक्षा । अगर आप अपनी सी० आई० डी० के द्वारा पता लगायें तो आपको मालूम होगा कि यह विश्वविद्यालय कम्युनिस्टों का अड्डा बन गया है । दूसरे स्थानों पर दूसरे तरह के कम्युनिस्ट होंगे, लेकिन अगर आपको कम्युनल कम्युनिस्ट देखने हों तो आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जाकर देख सकते हैं । इनकी स्थिति क्या है । इनकी स्थिति यह है कि यहां पर केरल दिवस मनाते हैं । "रेप इन केरल" नाम की किताबें बांटी जाती हैं । दलाई लामा हिन्दुस्तान में आए तो यहां पर एक सैमिनार बुलाया गया । लेकिन एक सब से खतरनाक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि चीन को भारत की उस भूमि पर जो उसने अपने अधिकार में ले रखी है अपना अधिकार साबित करने का प्रमाण मिल जाए, इसके लिए भारतवर्ष के पुराने दस्तावेजों को खोजने की कोशिश की जा रही है । ब्रिटिश पीरियड के तो कई ऐसे दस्तावेज नहीं मिल रहे है । इसलिए अब मुगलकाल के दस्तावेजों की खोज हो रही है । अगर आप अपनी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराएं तो आप मेरे इस कथन की पुष्टि पाएंगे कि इन मुगलकाल के दस्तावेजों की खोज अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ही हो रही हैं । जो इस पार्टी से विशेष रूप से सम्बन्धित हैं वह वहां आजकल हिस्ट्री के हैड आफ डिपार्टमेंट हैं, उनकी ही ओर से इस प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है । इसी विभाग के पहले अध्यक्ष ने एक किताब निकाली है जो मैं हाउस में दिखाना भी चाहता हूं, जो कि इसी प्रकार की मनोवृत्ति का परिचायक है । यह हजरत पहले हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैड थे, मुहम्मद हबीब नाम था, उन्होंने "यह सुलतान महमूद आफ गजनी" किताब लिखी है । यह किताब तो उन्होंने महमूद गजनवी के ऊपर लिखी है लेकिन इसको भेंट किया गया है चेयरमैन माओत्से तुंग को, कमांडर इन चीफ चूतेह को और प्रीमियर चाऊ एन लाई को । एक को नहीं बल्कि तीन-तीन को इसलिए पेश की गयी है कि कम्युनिस्ट देशों में क्या पता आज कौन है कल कौन आ जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बस करें । वे आध घंटे से ज्यादा बोल चुके हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बस मैं समाप्त किये देता हूं । आपकी इस अनुमति से मैं

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

इतना और कह कर समाप्त करूंगा कि इन सारी चीजों को संरक्षण इस समय विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति की ओर से दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में जब डा० जाकिर हुसैन वाइस चांसलर थे तो उस वक्त वह जरूर उसको एक राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते थे और मिली जुली संस्कृति का विकास करना चाहते थे लेकिन उनके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फिर से उसी पुराने ढंग पर चाल चलती जा रही है। इसलिए मैं अन्तिम बात यह कह कर समाप्त करता हूं कि जिस व्यक्ति ने इनक्वायरी कमेटी को सही काम नहीं करने दिया, जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री के संकेतों के बाद भी जांच समिति में बराबर बैठा, जिस व्यक्ति ने कमेटी को गवाही देने वालों को तरह तरह से परेशान किया, जिस व्यक्ति ने विश्वविद्यालय के धन का दुरुपयोग करवाया, जिस व्यक्ति ने ५२ बार गलत आपत्कालीन शक्तियों का प्रयोग किया, जो व्यक्ति समिति को छात्रों के परीक्षाफल और प्रवेश रिकार्ड पेश न कर सका, जिसके समय में हिसाब के रिकार्डों में फेर बदल होती रही, जिस व्यक्ति ने गलत नियुक्तियों के रिकार्ड तोड़ रखे हैं, जिस व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों को भर कर यूनिवर्सिटी को निजी सम्पत्ति बनाना चाहा, जो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी साम्यवादी गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है, जिस व्यक्ति के कारण अनेक योग्य प्रोफेसर वहां से छोड़ कर जा रहे हैं और जिस व्यक्ति के कारण युनिवर्सिटी के ढांचे से उसकी आत्मा निकलना चाहती है ऐसे व्यक्ति को तुरन्त विश्वविद्यालय से अलग किया जाय और फिर से राष्ट्रपति की ओर से विजिटर कमेटी नियुक्त करा कर जांच की जाय तभी आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय की रक्षा कर सकेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That this House takes note of the Report of the Aligarh Muslim University Enquiry Committee, laid on the Table of the House on the 21st April, 1961."

Now, the hon. Member has taken 33 minutes. At the most, if we do extend the time, we could go up to 3 o'clock.

Shrimati Renu Chakravartty: We will have to extend the time since he has taken so much time.

Mr. Deputy-Speaker: Is the House prepared to sit beyond five?

Several Hon. Members: Oh, yes.

Shri Kalika Singh (Azamgarh): The time should be extended.

Mr. Deputy-Speaker: We have to conclude this. If the House is prepared to sit longer I have no objection. Then we sit up to six o'clock. And we will take up the non-official business at 3-30.

Shri C. D. Pande (Naini Tal): The issue should be discussed without party considerations and prejudices.

Mr. Deputy-Speaker: There is an amendment to the motion.

Is it being moved?

Shri Balraj Madhok (New Delhi): Yes, Sir. I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"and feels that the enquiry was vitiated by the presence of the Vice-Chancellor of Aligarh University in the sitting of the Committee against the assurance to the contrary given by the Minister of Education on the floor of the House and by the atmosphere of terror created by certain interested parties as a result of which many intending witnesses did not appear before the Enquiry Committee."(1).

Mr. Deputy-Speaker: The amendment and the original motion are now before the House.

I have ten names with me and there must be about ten more who desire to participate. So the time-limit for each speaker may be ten minutes.

श्री मु० हि० रहमान (अमरोहा) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आज हाउस में कुछ दिनों के बाद फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है। हमारे मोहतरम श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने ३३ मिनट में इतनी बुराइयां बयान कर दी हैं कि अगर उसी के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूं तो बहुत वक्त चाहिए। लेकिन जाहिर है कि हाउस का वक्त बहुत ही बंधा हुआ है और उसमें कुछ उसूली बातें ही कही जा सकेंगी।

मुझे खूब याद है कि उस जमाने में शास्त्री जी ने युनिवर्सिटी के खिलाफ १९ इलजामात लगाये थे और मुझे खुशी है कि अगर्चे उन्होंने कहीं कहीं से जुमले जोड़ कर उससे कुछ मतलब निकाले हैं लेकिन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर बुनियादी तौर पर उन सब की तरदीद की गई है और उन सब को गलत कहा गया है।

पहले भी और अब भी बड़े जोर से चर्चा की गई है कि युनिवर्सिटी काबिले ऐतमाद नहीं है। वहां पर कम्युनिस्टों का जोर है और वहां पर कम्युनलिस्ट्स का जोर है। अब यह अजीब बात है क्योंकि जिस जगह पर कम्युनिस्ट्स का जोर हो वहां कम्युनलिस्ट्स का भी जोर हो यह समझ से परे की चीज है। दोनों चीजें मुतजाद हैं और एक जगह पर यह दोनों चीजें जमा नहीं हो सकतीं। कभी ऐसी बात नहीं हो सकती। एक तरफ तो उनको कम्युनिस्ट होने का इलजाम लगाया जाय और दूसरी तरफ उन पर कम्युनलिस्ट्स होने का इल्जाम लगाया जाय, यह खुद साबित करता है कि शायद इसके पीछे कुछ और मामला है जिसको कि वह शुरू में फरमा चुके हैं और दरहकीकत उसको बदनाम करने की एक खास साजिश है। मैं समझता हूं कि आज कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि युनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट्स या कम्युनलिस्ट्स का कोई अड्डा है। जहां तक ख्यालात की बात है तो तमाम युनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ खयालात के प्रोफेसर्स और टीचर्स होते हैं और अगर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में हैं तो यह कोई अजीबोगरीब बात तो नहीं है लेकिन वहां पर कोई अड्डा नहीं है।

अभी चीन की बात एक भयानक तरीके से चूंकि वक्त के करीब की बात थी, कही गई और इस बात को कहा गया कि जब ब्रिटिश पीरियड का कोई ऐसा मैप नहीं मिला कि चीन उसे सरहद के बारे में अपनाने की कोशिश करे तो मुगल पीरियड की तलाश की गयी हालांकि उनको भी मालूम होगा कि मुगल पीरियड से ही इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत मजबूत हो गयी है। औरंगजेब के जमाने में भी जो सरहदें चीन के और हमारे दरमियान थीं वह वही सरहदें हैं जिन को हम आज मान रहे हैं और जिसका कि इंकार चीन कर रहा है। प्रोफेसर साहब के खिलाफ यह कहना कि वह मुगल पीरियड के सबूत लेकर चीन की मदद कर रहे हैं कि जिससे आज हिन्दुस्तान को नुक्सान पहुंचे इससे ज्यादा बदगुमानी और इससे ज्यादा गलत और झूठ बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती।

इस बात का लिहाज आप खुद कर सकते है कि दो बुनियादी ऐतराजात जो किये गये उन दोनों बुनियादों की हैसियत क्या है और इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिन चन्द मामलात में जो इलजामात लगाये गये हैं उनकी भी हकीकत क्या है। आज यह कहा गया कि वह इनक्वायरी कमेटी इसलिये काबिले ऐतबार नहीं है कि वाइस

[श्री मु० हि० रहमान]

चांसलर बराबर उसमें बैठते रहे। मैं कहता हूं कि वाइस चांसलर का बैठना कोई कमीशन का जुज नहीं था और उसके लिए कोई जरूरी नहीं था।

वह उसका मेम्बर नहीं था। लेकिन मेम्बरान ने जो ऊंचे दर्जे की हैसियत रखते हैं उन्होंने आज यहां उन पर बेभरोसगी का इजहार लगाया और यह भी कहा कि वह काबिले एतबार नहीं हैं। अब इस तरह की दुनिया में कौन काबिले एतबार है? एक इनक्वायरी कमेटी बैठी वह इसलिये नाकाबिले एतबार और दूसरी इनक्वायरी कमेटी बैठी वह और वजह से नाकाबिले एतबार, इस तरीके से युनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए सिलसिला जारी रक्खा जाये, यह आपकी मंशा और आपकी खुशी मालूम होती है। हमारे मोहतरीम लीडर ने बिल्कुल आजादी के साथ अपना यह फैसला दिया और उस फैसले में उन्होंने कतन इजाजत नहीं दी कि उसमें वाइस चांसलर बैठें।

जहां तक बयानात का ताल्लुक है एक तरफ यह कहा जाता है कि बयानात देने वालों को दबाने की कोशिश की और इस तरीके से आम ऐलानात नहीं हुए। लेकिन बयानात बाहर से भी दिये गये और अन्दर भी बयानात दिये गये। आपने भी बाहर से बयान दिया और मैंने भी दिया और दूसरे लोगों ने भी बयान दिया। बाहर से भी बयान दिये गये और अन्दर से भी बयान दिये गये। आप उठा कर पूरी मिसल को देखिये, पूरी रिपोर्ट और तफसीलात को देखिये और तब आपको अन्दाजा होगा कि बनारस युनिवर्सिटी की इनक्वायरी कमेटी में या शायद किसी भी दूसरी युनिवर्सिटी की इनक्वायरी कमेटी में किसी उस्ताद, प्रोफेसर, तालिबिल्म और जो दीगर मुलाजिम हैं उनको इतनी आजादी बयान देने में न मिली होगी जितनी आजादी इसकी इनक्वायरी कमेटी के मौके पर उनको अपने स्टेटमेंट्स और शहादतें देते वक्त मिली थी। बिल्कुल आजादी के साथ उसके सामने बयानात और शहादतें दी गयीं, लेकिन यहां कहा गया कि उन को दबाने की कोशिश की जाती है। इस तरीके की बातों से दरहकीकत एक गलत-फहमी पैदा करना है। कमेटी ने साफ लफ्जों में कहा है कि कोई गबन और कोई तगल्लुब नहीं है। अलबत्ता उस ने चन्द टेक्नीकल बातों में कुछ रकमों का जिक्र किया है जिन को कि अपने खास अन्दाज से मेरे दोस्त शास्त्री जी ने करप्शन के तौर पर बयान करने की कोशिश की है हालांकि कमीशन ने कतई तौर पर साफ कहा है कि कोई गबन नहीं है कोई तगल्लुब नहीं है। अलबत्ता यह जरूर कहा है कि हिसाब रखने के ढंग में उस किस्म की जाब्तगियां पूरी तरह नहीं बरती जातीं जिन को कि बरता जाना चाहिये था। ठीक है अगर हिसाब रखने के ढंग में कोई खामी पायी गयी है तो उस को दुरुस्त होना चाहिये। आज गवर्नमेंट के हिसाबात में आडीटर साहब बहुत सी टेक्नीकल गलतियां निकालते हैं। ५०, ५० और १००, १०० टेक्नीकल गलतियां खुद गवर्नमेंट के हिसाब में बतलाई जाती हैं, लेकिन उस के माने यह थोड़े ही हो जाते हैं कि सरकार गबन कर रही है या करप्शन कर रही है। अब अगर वहां पर टेक्नीकल गलतियां बतलाई गई तो कौन सा जुर्म हो गया? टेक्नीकल गलती को दुरुस्त किया जाना चाहिये और उन को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है।

उन्हीं पुरानी बातों को आज फिर दुहराया जा रहा है जैसे गुलाम सैय्यदैन के मकान का किस्सा या जमीन का किस्सा। वही चीजें जो

पहले कही गयी थीं आज फिर उन का जिक्र किया जा रहा है। उन का साफ बेहतर से बेहतर निखरा हुआ जवाब पिछले मौका पर बाकायदा रिकार्ड के साथ बताया गया था। कुछ जमीनें ज्यादा से ज्यादा रिआयत के साथ खरीद की गयी थीं बजाय इस के कि उन को मंहगे भाव पर खरीदा गया होता और उन के वास्ते ज्यादा कीमतें दी गई होतीं जब कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बागों का हवाला दिया गया, दरख्तों का हवाला दिया गया। अगर इस तरीके से हवाले दिये जाने हैं, तो इस हाउस में चार पांच दिन का मौका दीजिये, ताकि कम से कम चार पांच सौ सफहे की रिपोर्ट आप के सामने रखी जाये और जो बातें आनरेबल मेम्बर ने कही हैं, उन की ताईद की जाये। एक बात को एक तरीके से कमेटी कहती है और उस का मतलब यह निकलता है कि कोई गबन, कोई तगल्लुब, कोई इस किस्म की ज्यादतियां नहीं हैं। लेकिन हां, कुछ टैक्नीकल गलतियां हैं और उन को आनरेबल मेम्बर किस तरह से बयान करते हैं? उन को इस तरह भयानक रूप में बयान करते हैं कि मालूम हो कि एक बहुत बड़ा गबन हो गया, लाखों रुपये का गबन हो गया, लूट हो रही है। ख्याल फरमाइये कि बात कहां से कहां पहुंची।

13hrs.

जहां तक एप्व इंटमेंट्स का ताल्लुक है, ग्यारह एप्वाइंटमेंट्स के बारे में एतराज किया गया, अगर्चे एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने उस की सराहत के साथ, दलील के साथ तरदीद करदी है कि ग्यारह एप्वाइंटमेंट्स भी काबिले-ऐतराज नहीं हैं। मगर मैं मान लेता हूं कि ग्यारह एप्वाइंटमेंट्स इस किस्म के हुए, जिन्हें काबिले ऐतराज कहा जा सकता है। अगर १२५० एप्वाइंटमेंट्स में से ग्यारह काबिले ऐतराज हुए, तो एक यूनिवर्सिटी नहीं, पचास यूनिवर्सिटीज में इस किस्म की बातें निकल सकती हैं और निकाली जा सकती हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात को एक भयानक नक्शे के साथ पेश कर के यह बताया जाये कि यूनिवर्सिटी का करेक्टर खराब हो गया है, यूनिवर्सिटी में बहुत गड़बड़ हो रही है और लाखों रुपये का गबन हो रहा है, यह मुनासिब नहीं है। इन तरीकों से यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता है—इस तरह से नाम ले कर और खास तौर पर हवाले दे कर यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता है।

आनरेबल मेम्बर ने इंजीनियरिंग के तुलेबा के बारे में जिक्र किया। जो डीटेल्ज उन्होंने दी है, वे पूरे तरीके से दुरुस्त हों, या न हों, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं—मुझे माफ किया जाये, इस में कोई कम्युनल सवाल नहीं है—कि मुल्क में दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम से है और दूसरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से है—यों तो यूनिवर्सिटीज बहुत हैं—तो मुझे बताया जाये कि १९४७ से इस वक्त तक बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में कितने उस्ताद मुसलमान रखे गये हैं और कितने उस्ताद वहां हैं और मुझे यह भी बताया जाये कि वहां पर मुसलमान तुलेबा कितने हैं और कुल तादाद कितनी है। (*Interruptions*) इस में हिन्दू-मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त एक तिहाई के करीब, जो कि अब आधे के करीब आ रहे हैं, उस्ताद और तालिब-इल्म गैर-मुस्लिम मौजूद हैं। ऐसी सूरत में जब कि उस यूनिवर्सिटी में, जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाती है, एक तिहाई से जायदा गैर-मुस्लिम तालिब-इल्म मौजूद हों, हर शोबे में मौजूद हों, टीचर्ज, प्रोफसर्ज, उस्ताद बड़ी तादाद में मौजूद हों, तो दूसरी यूनिवर्सिटी से जरा उस का मुकाबला कर के बतलायें कि आज कौन सी ऐसी मोनोपाली बना दी गई है मुसलमान तालिब-इल्मों के लिये, अगर चार पांच तालिब-इल्म वहां जायद आ जायें। सारे हिन्दुस्तान की एक युनिवर्सिटी में, एक मुसलमान यूनिवर्सिटी में अगर मान लिया जाये कि इत्तिफाक से चार तालिब-इल्म

[श्री मु० हि० रहमान]

ज्यादा आ जायें, तो क्या उस के मानी ये हैं कि उस में बेईमानी की गई, उस के मानी ये हैं कि मुसलमानों के लिये मोनोपली बना दी गई है, उस के मानी ये हैं कि मुसलमानों के लिये रिजर्वेशन हो गया है ? बयान का यह तरीका दुरुस्त नहीं है और न ही इस तरीके से हाउस में गलत बयानी होनी चाहिये ।

एप्वाइंटमेंट्स के सिलसिले में अभी यह जिक्र किया गया कि एक साहब थे, जिन को लकवा लग गया था, फालेज हो गया था और उन को एप्वाइंट कर लिया गया । आनरेबल मेम्बर को सराहत के साथ बता दिया गया है कि उन्होंने वह एप्वाइंटमेंट नहीं किया था बल्कि यू० जी० सी० ने उस की इजाजत दी थी । क्या यू० जी० सी० इस कद्र नाकाबिल और बेएतबार है ? मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिये न यू० जी० सी० काबिल-एतबार रहा, न कोई और इदारा रहा, न गवर्नमेंट आफ इंडिया रही, न एजूकेशन मिनिस्टर रहे, कोई भी न रहा तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेचारी क्या हुई कि उस की बदौलत सारे के सारे बेएतबार हो गये , पूरे मुल्क के जिम्मेदार आदमी बेएतबार हो गये । यह अजीब तरीका है । यू० जी० सी० ने उस आदमी की एप्वाइंटमेंट कराई और उस ने इजाजत दी। यह बात मौजूद है आनरेबल मेम्बर के सामने । जहां तक मैं समझता हूं, इस किस्म की बातों से यह मामला हल नहीं हो सकता है ।

बेशक मैं मानता हूं कि इस में इस्लाह की जरुरत है । कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन की इस्लाह होनी चाहिये । कौन सा इदारा है, जिस में कमजोरियां और खामियां नहीं हैं ? उन की इस्लाह होनी चाहिये । लेकिन इस तरीके से भयानक इल्जाम लगाना कि वहां पर इस तरीके से रिश्तेदारों के साथ नाजायज लेन-देन किया जा रहा है, वहां पर तुलेबा के नम्बरों के मामलों में गड़बड़ की जा रही है, ठीक नहीं है । तिब्बिया कालिज का भी जिक्र किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें हमारे पास भी हैं, सिर्फ आनरेबल मेम्बर के पास ही नहीं हैं । उन्होंने सारी की सारी तस्वीरें और नक्शे सब को बांटे हैं । लेकिन उस की एक रूदाद है और कहानी है । जिन लोगों ने आनरेबल मेम्बर को पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, उन्होंने गलत इल्जामात लगाने के लिये बात नहीं बताई है । जहां तक दवाओं का ताल्लुक है, उन की सूरत अलग है । उन की कीमत का मामला जुदा है । उस में जेब में रुपया डालने का मामला कतई नहीं है । यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है । मैं पूरी तहरीर के बाद यह बात कर रहा हूं । मैं एक्जीक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर हूं । मुझे उस की तफसीलात मालूम हैं । अगर मुझे वक्त दिया जाये तो, मैं सारी तफसीलात दे सकता हूं। दस मिनट में मैं आप को क्या बता सकता हूं ।

उसूली तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जो बातें कही गई हैं, उन में से एक बात भी सही नहीं मानी गई । बुनियादी बातों के बारे में यह कहा गया है कि वे गलत हैं, और न वहां पर गबन है, न नेशनल करेक्टर का फर्क है,न तुलेबा के बारे में कोई रिजर्वेशन है और न दूसरी चीजों के बारे में कोई गड़बड़ है । इस से अन्दाजा हो सकता है कि आनरेबल मेम्बर की दूसरी बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत-बयानी की गई है और कितना यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है ।

जहां तक प्रो-वाइस-चांसलर का सवाल है, मैं भी आनरेबल मेम्बर के साथ हूं । वाइस-चांसलर यूनिवर्सिटी में है और प्रो-वाइस-चांसलर उसकी मदद करता है । रेक्टर की शक्ल नहीं होनी चाहिये । एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने मुत्तिफिका तौर पर यह तय किया है । बनारस यूनिवर्सिटी में भी प्रो-वाइस-चांसलर है, हमारे यहां भी रहे ।

आज जुम्मे का दिन है। इसलिये मैं ने पहले तकरीर करने की इजाजत आप से चाही है। मुमकिन है कि दूसरे साहबान भी बयान करें। अगर दोनों में से किसी तरफ से भी किसी को रियाकारी का इल्जाम दिया जाये, कम्युनलिस्ट या कम्युनिस्ट अड्डा बताया जाये, तो वह महज पार्टीबाजी है, दलबन्दी है और बाज प्रोफसरों और उस्तादों की कनवर्सिंग और साजिशों का नतीजा है, जो अपना मफाद देखते हुए यूनिवर्सिटी के मफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहरहाल दोनों बातें गलत हैं। यूनिवर्सिटी का बेहतरीन नेशनल करेक्टर है और वह आगे बढ़ रही है। हम जैसे आदमी उस में जद्दो-जहद करते हैं और उस को ज्यादा से ज्यादा सैकुलर लाइन पर ला रहे हैं। यह यकीन दिलाते हैं कि हम उस को किसी भी तरीके से न कम्यूनलिज्म का और न कम्युनिज्म का अड्डा बनने देंगे और उस का करेक्टर बेहतरीन नेशनल करेक्टर रहेगा।

[محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب -

آج ہاؤس میں کچھ دنوں کے بعد یہ مسلم یونیورسٹی کی چرچا ہو رہی ہے - ہمارے محترم شری پرکاش ویر شاستری نے ۳۳ منٹ میں اتنی برائیاں بیان کر دی ہیں کہ اگر اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں تو بہت وقت چاہیئے - لیکن ظاہر ہے کہ ہاؤس کا وقت بہت ہی بندھا ہوا ہے اور اس میں کچھ اصولی باتیں ہی کہی جا سکیں گی -

مجھے خوب یاد ہے کہ اس زمانے میں شاستری جی نے یونیورسٹی کے خلاف ۱۹ الزامات لگائے تھے اور مجھے خوشی ہے کہ اگرچہ ان ہوں نے کہیں کہیں سے جملہ جوڑ کر اس سے کچھ مطلب نکالے ہیں لیکن انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے اندر بنیادی طور پر ان سب کی تردید کی گئی ہے اور ان سب کو غلط کہا گیا ہے -

پہلے بھی اور اب بھی بڑے زور سے چرچہ کی گئی ہے کہ یونیورسٹی قابل اعتماد نہیں ہے - وہاں پر کمیونسٹس کا زور ہے اور وہاں پر کمیونلسٹس کا زور ہے - اب یہ عجیب بات ہے کیونکہ جس جگہ پر کمیونسٹس کا زور ہو وہاں کمیونلسٹس کا بھی زور ہو یہ سمجھ سے پرے کی چیز ہے - دونوں چیزیں متضاد ہیں اور ایک جگہ پر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں - کبھی ایسی بات نہیں ہو سکتی - ایک طرف تو ان کو کمیونسٹ ہونے کا الزام لگا یا جائے اور دوسری طرف ان پر کمیونلسٹس ہونے کا الزام لگایا جائے یہ خود ثابت کرتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ ہے جس کو کہ وہ شروع میں فرما چکے ہیں اور در حقیقت اس کو بدنام کرنے کی ایک خاص سازش ہے - میں سمجھتا ہوں کہ

اس سے زیادہ غلط اور جھوٹ بات اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی -

اس بات کا لحاظ آپ خود کر سکتے ہیں کہ دو بنیادی اعتراضات جو کئے گئے ان دونوں بنیادوں کی حیثیت کیا ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن چند معاملات میں الزامات لگائے گئے ہیں ان کی بھی حقیقت کیا ہے - آج یہ کہا گیا ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی اس لئے قابل اعتبار نہیں ہے کہ وائس چانسلر برابر اس میں بیٹھتے رہے - میں کہتا ہوں کہ وائس چانسلر کا بیٹھنا کوئی کمیشن کا جز نہیں تھا اور اس کے لئے کوئی ضروری نہیں تھا - وہ اس کا ممبر نہیں تھا - لیکن ممبران نے جو اونچے درجے کی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے آج یہاں ان پر بے بھروسگی کا الزام لگایا اور یہ بھی کہا کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہیں - اب اس طرح تو دنیا میں کون قابل اعتبار ہے - لیکن انکوائری کمیٹی بیٹھی وہ اس لئے نا قابل اعتبار اور دوسری کمیٹی بیٹھی وہ اور وجہ سے نا قابل اعتبار اس طریقے سے یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لئے سلسلہ جاری رکھا جائے یہ آپ کی منشاء اور آپ کی خوشی معلوم ہوتی ہے - ہمارے محترم لیڈر نے آزادی کے ساتھ اپنا یہ فیصلہ دیا اور

[شری ایم - ایچ - رحمان]

آج کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یونیورسٹی میں کمیونسٹس یا کمیونلسٹس کا کوئی اڈہ ہے - جہاں تک خیالات کی بات ہے تو تمام یونیورسٹیوں میں مختلف خیالات کے پروفیسرس اور ٹیچرس ہوتے ہیں اور اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہیں تو یہ کوئی عجیب و غریب بات تو نہیں ہے لیکن وہاں پر کوئی اڈہ نہیں ہے -

اپنی چین کی بات ایک بھیانک طریقے سے چونکہ وقت کے قریب کی بات تھی کہی گئی اور اس بات کو کہا گیا کہ جب بریٹش پیریڈ کا کوئی ایسا میپ نہیں ملا کہ چین اسے سرحد کے بارے میں اپنانے کی کوشش کرے تو مغل پیریڈ کی تلاش کی گئی حالانکہ ان کو بھی معلوم ہوگا کہ مغل پیریڈ سے ہی اس وقت ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے- اورنگ زیب کے زمانے میں بھی چو سرحدیں چین کے اور ہمارے درمیان تھیں وہ وہی سرحدیں ہیں جن کو کہ ہم آج مان رہے ہیں اور جس کا کہ انکار چین کر رہا ہے - اس بنا پر پروفیسر صاحب کے خلاف یہ کہنا کہ وہ مغل پیریڈ کے ثبوت لے کر چین کی مدد کر رہے ہیں کہ جس سے آج ہندوستان کو نقصان پہنچے اس سے زیادہ بد گمانی اور

اس فیصلہ میں انہوں نے قطعاً اجازت نہیں دی کہ اس میں وائس چانسلر بیٹھیں -

جہاں تک بیانات کا تعلق ہے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بیانات دینے والوں کو دبانے کی کوشش کی اور اس طریقے سے عام اعلانات نہیں ہوئے - لیکن بیانات باہر سے بھی دئے گئے اور اندر بھی بیانات دئے گئے - آپ نے بھی باہر سے بیان دیا اور میں نے بھی دیا اور دوسرے لوگوں نے بھی بیان دیا - باہر سے بھی بیان دئے گئے اور اندر سے بھی بیان دئے گئے - آپ اٹھا کر پوری مسل کو دیکھئے پوری رپورٹ اور تفصیلات کو دیکھئے اور تب آپ کو اندازہ ہو گا کہ بنارس یونیورسٹی کی انکوائری کمیٹی میں یا شاید کسی بھی دوسری یونیورسٹی کی انکوائری کمیٹی میں کسی استاد پروفیسر - طالب علم اور جو دیگر ملازم ہیں ان کو اتنی آزادی بیان دینے میں نہ ملی ہوگی - جتنی آزادی کہ اس کی انکوائری کمیٹی کے موقعہ پر ان کو اپنے اسٹیٹمنٹس اور شہادتیں دیتے وقت ملی تھی - بالکل آزادی کے ساتھ اس کے سامنے بیانات اور شہادتیں دی گئیں - لیکن یہاں کہا گیا کہ ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے - اس طریقے کی باتوں سے درحقیقت ایک غلط فہمی پیدا کرنا ہے - کمیٹی نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ کوئی غبن نہیں ہے کوئی تغلب نہیں ہے - البتہ اس نے چند ٹیکنیکل باتوں میں کچھ رقموں کا ذکر کیا ہے جن کو کہ اپنے خاص انداز سے میرے دوست شاستری جی نے کرپشن کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے - حالانکہ کمیشن نے قطعی طور پر صاف کہا ہے کہ کوئی غبن نہیں ہے کوئی تغلب نہیں ہے - البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ حساب رکھنے کے ڈھنگ میں اس قسم کی ضابطگیاں پوری طرح نہیں برتی جاتیں جن کو کہ برتا جانا چاہیئے تھا - ٹھیک ہے اگر حساب رکھنے کے ڈھنگ میں کوئی خامی پائی گئی ہے تو اس کو درست ہونا چاہیئے - آج گورنمنٹ کے حسابات میں آڈیٹر صاحب بہت سی ٹیکنکل غلطیاں نکالتے ہیں - ۵۰ - ۵۰ اور ۱۰۰ - ۱۰۰ ٹیکنکل غلطیاں خود گورنمنٹ کے حسابات میں بتلائی جاتی ہیں لیکن اس کے معنی یہ تھوڑے ہی ہو جاتے ہیں کہ سرکار غبن کر رہی ہے یا کرپشن کر رہی ہے - اب اگر وہاں پر ٹیکنکل غلطیاں بتلائی گئیں تو کون سا جرم ہو گیا - ٹیکنکل غلطیوں کو درست کیا جانا چاہیئے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے - انہیں پرانی باتوں کو آج پھر دوہرایا جا رہا ہے جیسے غلام السیدین کے مکان کا قصہ یا زمین کا قصہ - وہی چیزیں جو پہلے کہی گئی تھیں آج پھر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے - ان کا صاف بہتر سے بہتر

[شری ایم - ایچ - رحمان]

کونسل نے اس کی صراحت کے ساتھ - دلیل کے ساتھ تردید کر دی ہے کہ یہ گیارہ ایپوائنٹمینٹس بھی قابل اعتراض نہیں ہیں - مگر میں مان لیتا ہوں کہ گیارہ ایپوائنٹمینٹس اس قسم کے ہوئے جنھیں قابل اعتراض کہا جا سکتا ہے - اگر ۱۲۵۰ ایپوائنٹمینٹس میں سے گیارہ قابل اعتراض ہوئے - تو ایک یونیورسیٹی نہیں پچاس یونیورسیٹیز میں اس قسم کی باتیں نکل سکتی ہیں اور نکالی جا سکتی ہیں - میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات کو ایک بھیانک نقشے کے ساتھ پیش کرکے یہ بتایا جائے کہ یونیورسیٹی کا کیریکٹر خراب ہو گیا ہے - یونیورسیٹی میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے اور لاکھوں روپیئے کا غبن ہو رہا ہے - یہ مناسب نہیں ہے - ان طریقوں سے یونیورسیٹی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا ہے - اس طرح سے نام لے کر اور خاص طور پر حوالے دے کر یونیورسیٹی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا ہے -

آنریبل ممبر نے انجینیرنگ کے طلبا کے بارے میں ذکر کیا - جو ڈیٹیلز انہوں نے دی ہیں وہ پورے طریقے سے درست ہوں یا نہ ہوں - لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں—مجھے معاف کیا جائے — اس میں کوئی کمیونل سوال نہیں ہے — کہ ملک میں دو یونیورسیٹیز ہیں—ایک ہندو نکھرا ہوا جواب پچھلے موقع پر باقاعدہ ریکارڈ کے ساتھ بتا دیا گیا تھا - کچھ زمینیں زیادہ سے زیادہ رعایت کے ساتھ خرید کی گئی تھیں بجائے اس کے کہ ان کو مہنگے بھاؤ پر خریدا گیا ہوتا اور ان کے واسطے زیادہ سے زیادہ قیمتیں دی گئی ہوتیں جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوا باغوں کا حوالہ دیا گیا اور درختوں کا حوالہ دیا گیا - اگر اس طریقے سے حوالے دئے جاتے ہیں تو اس ہاؤس میں چار پانچ دن کا موقع دیجئے تاکہ کم از کم چار پانچ سو صفحے کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی جائے اور جو باتیں آنریبل ممبر نے کہی ہیں - ان کی تردید کی جائے - ایک بات کو ایک طریقے سے کمیٹی کہتی ہے اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی غبن - کوئی تغلب - کوئی اس قسم کی زیادتیاں نہیں ہیں - لیکن - ہاں - کچھ تھکایکل غلطیاں ہیں اور ان کو آنریبل ممبر کس طرح سے بیان کرتے ہیں - ان کو وہ اس طرح بھیانک روپ میں بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہو کہ ایک بہت بڑا غبن ہو گیا - لاکھوں روپیئے کا غبن ہو گیا - لوٹ ہو رہی ہے - خیال فرمایئے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی -

13 hrs.

جہاں تک ایپوائنٹمینٹس کا تعلق ہے - گیارہ ایپوائنٹمینٹس کے بارے میں اعتراض کیا گیا - اگر یہ ایکسیکیوٹو

یونیورسیٹی کے نام سے ہے اور دوسری
مسلم یونیورسیٹی کے نام سے ہے — یوں
تو یونیورسیٹیز تو بہت ہیں ——
تو مجھے بتایا جائے کہ ۱۹۴۷ سے
اس وقت تک بنارس ہندو یونیورسیٹی
میں کتنے استاد مسلمان رکھے گئے
ہیں اور کتنے استاد وہاں ہیں اور
مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ وہاں
پر مسلمان طلبا کتنے ہیں اور کل
تعداد کتنی ہے . . .

اس میں ہندو مسلم کا کوئی سوال
نہیں ہے - میں بتانا چاہتا ہوں
کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اس
وقت ایک تہائی کے قریب - جو کہ
اب آدھے کے قریب جا رہے ہیں -
استاد اور طالب علم غیر مسلم موجود
ہیں - ایسی صورت میں جب کہ
اس یونیورسٹی میں - جو کہ مسلم
یونیورسٹی کہلاتی ہے - ایک تہائی
سے زاید غیر مسلم طالب علم موجود
ہوں - ہر شعبے میں موجود ہوں -
ٹیچرز پروفیسرز اور استاد بڑی تعداد
ٹیچرز پروفیسرز اور استاد بڑی تعداد
میں موجود ہوں تو دوسری یونیورسٹی
سے اس کا مقابلہ کر کے بتائیں کہ
آج کون سی ایسی مانوپلی بنا
دی گئی ہے مسلمان طالب علموں
کے لئے - اگر چار پانچ طالب علم
وہاں زاید آ جائیں - سارے ہندوستان
کی ایک یونیورسٹی میں - ایک
مسلم یونیورسٹی میں - اگر مان لیا
جائے کہ اتفاق سے چار پانچ طالب
علم زیادہ آ جائیں تو کیا اس کے
معنی یہ ہیں کہ اس میں بے ایمانی
کی گئی - کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ
مسلمانوں کے لئے مانوپلی بنا دی گئی
ہے - کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ
مسلمانوں کے لئے ریزرویشن ہوگیا ہے -
بیان کا یہ طریقہ درست نہیں ہے اور
نہ ہی اس طریقہ سے ہاؤس میں غلط
بیانی ہونی چاہئے - (*Interuptions*)

ایپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں ابھی
یہ ذکر کیا گیا کہ ایک صاحب تھے
جن کو لقوہ لگ گیا تھا - فالج ہو گیا
تھا اور ان کو اپوائنٹ کر لیا گیا -
آنریبل ممبر کو صراحت کے ساتھ بتا
دیا گیا ہے کہ انہوں نے وہ ایپوائنٹمنٹ
نہیں کیا تھا بلکہ یو - جی - سی -
نے اس کی اجازت دی تھی - کیا یو -
جی - سی اس قدر ناقابل اور بے اعتبار
ہے - کیا مسلم یونیورسیٹی کے لئے نہ
یو - جی - سی - قابل اعتبار رہا - نہ
کوئی ادارہ رہا - نہ گورنمنٹ آف
انڈیا رہی - نہ ایجوکیشن منسٹر رہے -
کوئی بھی نہ رہا - تو مسلم یونیورسیٹی
بے چاری کیا ہوئی کہ اسکی بدولت
سارے کے سارے بے اعتبار ہوگئے - پورے
ملک کے ذمہ وار آدمی بے اعتبار ہو
گئے - یہ عجیب طریقہ ہے - یو - جی -
سی - نے اس آدمی کی ایپوائنٹمنٹ
کرائی اور اس نے اجازت دی - یہ بات
موجود ہے آنریبل ممبر کے سامنے -
جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس قسم

مجھے اسکی تفصیلات معلوم ہیں - اگر مجھے وقت دیا جائے تو میں ساری تفصیلات دے سکتا ہوں - دس منٹ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں -

اصولی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو باتیں کہی گئی ہیں - ان میں سے ایک بات بھی صحیح نہیں مانی گئی ہے - بنیادی باتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ غلط ہیں اور نہ وہاں پر غبن ہے - نہ نیپوٹزم کیرکٹر کا فرق ہے - نہ طلبا کے بارے میں کوئی ریزرویشن ہے اور نہ دوسری چیزوں کے بارے میں کوئی کرپٹ ہے - اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنریبل ممبر کی دوسری باتیں کتنی صحیح ہیں - کتنی غلط بیانی کی گئی ہے اور کتنا یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے -

جہاں تک پرووائس چانسلر کا سوال ہے میں بھی آنریبل ممبر کے ساتھ ہوں - وائس چانسلر یونیورسیٹی میں ہے اور پرووائس چانسلر اسکی مدد کرتا ہے - ریکٹر کی شکل نہیں ہونی چاہئے - ایکسیکیوٹو کونسل نے متفقہ طور پر یہ طے کیا ہے - بنارس یونیورسیٹی میں بھی پرو وائس چانسلر ہے - ہمارے یہاں بھی رہے -

آج جمعہ کا دن ہے - اس لئے میں نے پہلے تقریر کرنے کی اجازت آپ سے

[شری ایم - ایچ - رحمان]

کی باتوں سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا ہے -

بیشک میں مانتا ہوں کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے - کچھ ایسی چیزیں ہیں- جنکی اصلاح ہونی چاہئے- کون سا ادارہ ہے جس میں کمزوریاں اور خامیاں نہیں ہیں - ان کی اصلاح کرنی چاہئے - لیکن اس طریقے سے بھیانک الزامات لگانا کہ وہاں پر اس طریقے سے رشتہداروں کے ساتھ ناجائز لین دین کیا جا رہا - وہاں پر طلبا کے نمبروں کے معاملے میں گڑبڑ کی جا رہی ہے - ٹھیک نہیں ہے - طبیہ کالیج کا بھی ذکر کیا گیا - میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں - صرف آنریبل ممبر کے پاس ہی نہیں ہیں - انہوں نے ساری کی ساری تصویریں اور نقشے سب کو بانٹے ہیں - لیکن اسکی ایک روداد ہے اور کہانی ہے - جن لوگوں نے آنریبل ممبر کو پڑھایا ہے - بتایا ہے - سمجھایا ہے - انہوں نے غلط الزامات لگانے کے لئے صحیح بات نہیں بتائی ہے -

جہاں تک دواؤں کا تعلق ہے - ان کی صورت الگ ہے - ان کی قیمت کا معاملہ جدا ہے - اس میں جیب میں ڈالنے کا معاملہ قطعی نہیں ہے - یہ بالکل درست نہیں ہے - میں پوری تحقیق کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں - میں ایکسیکیوٹو کونسل کا ممبر ہوں -

چاہی ہے - ممکن ہے کہ دوسرے صاحبان بھی بیان کریں - اگر دنوں میں سے کسی طرف سے بھی کسی کو ریاکاری کا الزام دیا جائے - کمیونلسٹ یا کمیونسٹ اڑہ بتایا جائے تو وہ محض پارٹی بازی ہے - دل بلدی ہے اور بعض پروفیسروں اور استادوں کی کنویسنگ اور سازشوں کا نتیجہ ہے - جو اپلا مفاد دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کے مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یونیورسیٹی کا مفاد نہیں دیکھ رہے ہیں - بہرحال دونوں باتیں غلط ہیں - یونیورسیٹی کا نیشنل بہترین کیریکٹر ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے - ہم جیسے آدمی اس جد و جہد کرتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیکولر لائن پر لا رہے ہیں - ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اسکو کسی بھی طریقے سے نہ کمیونلزم کا اور نہ کمیونزم کا اڈہ بننے دینگے اور اس کا کیریکٹر بہترین نیشنل کیریکٹر رہیگا -]

Shrimati Renu Chakravartty: Mr. Deputy-Speaker, Sir, we have just now heard the eloquent speech of Mr. Prakash Vir Shastri, who earlier also in a Half-an-Hour discussion, followed by a much longer speech by Mr. Vajpayee, in the same month of March 1960, had made various allegations against the Aligarh Muslim University.

Now, after that what has happened? A Committee was appointed which went in to the entire matter and many of the most sensational allegations which were made during those debates have not been found to be true. Now these gentlemen are rather angry about this Committee itself. They have now raised the question as to whether the Vice-Chancellor should have been present or not. The Committee itself admits that the Vice-Chancellor was present, but he was not present when the final findings were formulated and voted upon. It is there in the report of the Committee.

This very same Committee called upon Mr. Prakash Vir Shastri and afforded him a full opportunity of placing before them all the information in his possession, supported by the records he had. I do not see any reason why when he appeared before it he did not place before them all the documents he had containing substantiated and unsubstantiated material and got their opinion on them.

The real fact of the matter is that on the whole this enquiry committee has made a fairly good report, not only from the point of view of the Aligarh Muslim University but also other universities. It has provided food for thought for many other Universities. I do not at all say that many things were not wrong with the Aligarh Muslim University, we have seen how many things were wrong with the Banaras Hindu University. Standing here as an alumnus of the Calcutta University, I can say, that if we were to go into its affairs, or affairs of any other university, in the matter of appointments, or financial matters, we will find many similarities between the conditions prevailing there and those obtaining in the Aligarh University. Therefore, it is a good thing that one University gives us food for thought about other universities as well. But, I cannot appreciate this fact that the University is charged with some sensational things which are proved to be absolutely incorrect. I can assure this House that people outside and even amongst many of us, certain things have stuck

[Shrimati Renu Chakravartty]

in our mind, these things are the most sensational points that were made during these debates. One was the question that machinery bought there was being sent to Pakistan. It stuck in our minds. How can you take it away from our mind? This Committee says that it is an absolutely baseless allegation.

Again, we find that many charges were made about Mr. Zaidi's property—Mr. Zaidi is a person who is known as a nationalist Muslim, a person who has been in high and responsible positions in the Education Ministry—about his house, how he made a lot of money on that, etc. That was what was alleged in this House. I have gone through the entire proceedings of the enquiry committee. It is not a fact that so many square inches were worth 25 naya paise. The C.P.W.D. expert has given us three formulae. Out of the three, he has said that the last one, that is the basis on which calculation is made for municipal taxation, is not dependable. The other two formulae are very complicated. He has said that even according to them, the purchase of Mr. Zaidi's property and Mr. Khwaja's property was absolutely in order —they have condoned it. Upon the figures that have been given to us, for a layman who has no common axe to grind, it is an absolutely clear case that there was nothing irregular about it. These are the three or four things that have stuck in our minds. As the Committee has correctly pointed out, just to answer rumours does not take away the bad effects which are left by such mud-slinging. Therefore, I feel from that point of view, to say that this is a nest of anti-national people who are sending away property belonging to the University to Pakistan, that Ranikhet where they acquired property was a centre of Pakistani agents, really worries us.

After all, as I pointed out during the debate on the Demands for Grants of the Education Ministry, we cannot forget the past history of the Aligarh University. It was on the Muslim League basis. Therefore, we have to foster it. We have to foster it with very great care and see that it does not become a centre of past tradition. The Committee says here:

> "There is a lurking fear in some quarters that the Aligarh Muslim University might once again revert to its former mood which accepted partition based on the theory of two separate nations. It is his suspicion that tends to lend exaggerated importance to reports about some of the activities of the campus.

Then, they go on to tell us about the rumours about sending machinery to Pakistan.

> "This, we found, was a totally baseless allegation. Similarly wild allegations regarding anti-national activity on the campus disturb the public mind, but leave the University helpless. The denial of such rumours is not always readily possible, nor does it carry conviction to minds already prejudiced.

I won't read out the findings on these allegations because they are there before the House.

The second reason why I think that this enquiry report isa good one is because it has dealt with certain aspects of the way how we should try to develop a national integrated outlook in our Universities. It has dealt with this. It is a difficult problem In a situation when communalism is abroad, there is an attempt by both parties—Muslim communalists and Hindu communalists—try to dub everybody who is secular as a communalist. That is there. That is what is being done. I have been recently to Jabalpur. I have seen the tricks over there. I have seen Saugor. I have seen in this House also. As my friend Shri M. H. Rahman rightly pointed out, we are told that we do not believe in God and we do not have any

religion. At the same time, we are told that we are communalists, communists and communalists both together. This is a very famous trick. We all know about it.

Actually, the situation has changed after Independence. The two-nation theory has been completely rejected by our country. As this Enquiry committee says, we must inculcate a sense of responsibility to the community at large and loyalty to the State. Beyond these two things, there must be academic freedom and the struggle should be to fight out communal ideas, revivalist theories which, whether through the name of tradition or theology, seeks to stultify and rigidify our outlook and create divisions in our country. At the same time, there must be preservation of the good in the past tradition of the University. The two things have to be combined if we really want to keep a good and healthy atmosphere and preserve all the best in our tradition. That is why I would like to say that we should study what has been said by this Committee on page 142. They have dealt with this question of tradition. They have told us that many Muslim friends came and gave evidence. What was Muslim tradition? What is it? Let us understand what that tradition is. Finally, they have said in excellent words:

> "In our opinion, apart from standing for those things, every university must recognise as true objectives of university education, it should develop and emphasise the study of what we may describe as the contribution of the Muslim community to the complex pattern of our national culture, and in fact to the worldwide culture of humanity."

They go on to say that a specially privileged position is there for the Aligarh University to foster that emotional integration which is essential for the preservation of India's cultural and political unity. That is why they say,

> " . . . the Muslim University, Aligarh should build up strong departments for the study of languages associated with Muslim culture such as Arabic, Persian and Urdu. It should have a strong department of History which should pay special attention to the contributions which Islam has made not only to world history but also to the development of Indian polity, Indian thought and Indian art . . . It is in the hope that the Muslim University, Aligarh will rise to the challenge of today that we have undertaken this task . . ."

This is a very important outlook. This is the outlook which we have to foster in our country, in our universities, even in the Hindu University. Let there be a Hindu University. Let it be integrated with the total integration and unity of India.

Of special importance is the fact that our friend has raised this question, but he has not dealt with it, because he cannot deal with it. His outlook is also tinged with communalism. That is why he does not deal with this point. Our friend Shri M. H. Rahman was of course a bit afraid that we should touch the other communalists. But, we must show that if we are to build up this integrated approach in the departments that exist in the university, there must be efforts to see that no longer we allow the two-nation theory to prevail that we do find there. Just as we find Hindu communalists attacking some one else, even in the Aligarh University there are people who are doing it. We should see that it is not done. I am afraid I have no time; otherwise it would have been very good if I could read out how the Urdu press, the Jamaet-i- Islami have been attacking many things as we talk here about secularisation of **education there**

An Hon. Member: There is the book.

Shrimati Renu Chakravartty: The book is written by somebody else. The book is writtten by a historian of the University.

They say that the ideology of the Aligarh University by which they mean Muslim orthodoxy should be the ideology of the institution. Especially, there has been a small pamphlet, S.O.S. for Aligarh Muslim University, written by many of those Muslim communalists also to say whatever aid the University might receive from the Government and whatever control the Government might exercise —what is more important is not this small pamphlet. The University itself is bringing out with University funds a paper which is called Fikr O Nazar. It is an official publication of the University. It is run on University funds. At the very first stage, this was run by the Pro-Vice-Chancellor Dr. Yusuf Hussain Khan. He brought this out first; he made himself the editor and had published it for two years. In the very first issue he has announced that its purpose is the study and propagation of Muslim culture and traditions. That is all right. And he himself wrote a long article in it entitled 'The Rise and Fall of Humanism' in which he ran down Humanism and the principles of reason and progress. He is entitled to his views, even though such things should not be there in an official publication run by the university. However that be, he speak at the same time of Muslim *quam* and declares that whatever aid the university might receive from Government and however much authority Government might exercise over it, just because it is a Muslim university, it is answerable in theological and moral questions to the Muslim nation or the Muslim *quam*. These are things which we feel that it is very wrong for an official publication of the university to contain. This is what is contained in *Fikr-O-Nazar*, *April*, 1961.

Then, again, I should like to point out what Professor Rashid A Siddiqui has written. Then, there is a book called *The History of the Freedom Movement of Pakistan*, which has been written by one Mr. Khaliq Ahmad Nizami, Reader in History. There, he has written that:

> "As Shah Waliulaah's opposition to the Maratha movement was not an end in itself so also his descendant did not deem a struggle with the Sikhs an end in itself. It was a means to the creation of a favourable atmosphere for founding an ideal homeland for the Muslims in which the *Khilafat-i-Rashida* lives and works."

He says that that is the homeland for the Muslims and so on and so forth. This idea of the homeland of the Muslims, this idea of the two *quams* etc. are things which we think should not be permitted to continue in the Aligarh University, because we want that there sholud be more and more national integration, and in all our thought a national outlook should be fostered. I have no time to go into the other revivalist traditions that are there.

I am told that even in cultural functions, girls and boys are not permitted to have joint plays. In many of our universities, we allow it. And the funny things is that in the Enquiry Committee's Report, a very good chit is given to the students; a good chit is given to the students saying that they have heard so much about indiscipline, and they have compared it with what obtains in the Banaras Hindu University, and they have said that as far as the students in the Aligarh University are concerned, they have shown exemplary restraint and discipline.

There is just one more point that I would like to make and that is regarding the question of communists. I do not know what Dr. Habib had in mind when he wrote that book.

Shri Ansar Harvani (Fatehpur): He wrote it in 1950.

Shrimati Renu Chakravartty: Yes, it looked like a very old book, as I was going through it. But this is the habit. I thought that at that time nobody thought that it was very wrong, and at that time he was given a post.

Shri Goray (Poona): The Chinese revolution is not so old.

Shrimati Renu Chakravartty: We thought that at that time nobody considered that it was very wrong. But today when we are in dispute with China, to raise a point of it is really a very funny thing, and, therefore, the point raised by Shri Prakash Vir Shastri in this regard should be treated with the lightness that it deserves.

He has also accused many professors there of being communists. The reason is very clear. Of course, there are Marxists, there are communists and there are socialists in our universities. Are you going to have only Sanghis and Hindu Mahasabha people in the Aligarh Muslim University? I wish to know why the Jan Sanghis and the Hindu Mahasabha people should consider themselves as the sole repositories of all patriotism and nationalism.

Shri Indrajit Gupta (Calcutta—South-West): Wisdom also.

Shrimati Renu Chakravartty: Finally, I wish to refer only to the excellent minute of dissent by Shri P. N. Sapru. Probably, my hon. friend is very angry that Shri P. N. Sapru's name was added to this enquiry committee. Shri P. N. Sapru has quoted chapter and verse in his minute of dissent. He has not quoted Mao Tse Tung; he has not quoted Mr. Khruschev; but he has quoted from the U.S.A., from Mr. Justice Frank Furter, from the Liberal Party of England and various others. I would not read out the other parts, but I would like to quote just one particular portion, because this will go down on record. He says:

> "I hope I have made it clear that in my opinion it would be completely wrong to ban political speculation, thought or activity in a university. Professors in western countries have made important contributions to social theory. Who can deny that Sydney Webb, Graham Wallas, T. H. Greene, R. L. Tawney, L. T. Hobhouse, Ramsay Muir, Alfred Marshall, J. M. Keynes, Harold Laski . . ."

—please note that Harold Laski's name is also there—

> ". . . G. D. H. Cole, A. V. Dicey, F. W. Maitland and A. C. Pigou, to mention only a few among a host of thinkers.".

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member has been addressing Shri Prakash Vir Shastri only and not myself.

Shrimati Renu Chakravartty: I am sorry. He was so eloquent, and, therefore, I was carried away by that. I apologise to you.

There, Shri P. N. Sapru has raised a very important point, namely that universities are places where within the limitations of banning an agitational approach, everything else should be permitted, because thought or knowledge is something that grows; all ideas should be permitted to be taught and to be discussed, because that is the way that all knowledge grows.

Here, I would like to point out the mischievous way in which Shri Vajpayee had raised some points. He had raised here a point about a question paper which contained a series of questions on Marxist philosophy, and he read out those questions, as if these were the only things that were taught in a philosophy or in a history. And yet the answer shows that this was

[Shrimati Renu Chakravartty]

only a part of that particular paper containing questions on the Marxist philosophy, and there were other philosophies also, but that was not pointed out by my hon. friend. Then, he raised a point about the question regarding the Kerala Education Act, and he asked why university professors and teachers should bother about whether the Kerala Education Act was good or bad; and it seemed as if only university professors and university teachers were of that opinion; but he forgot that Mr. Patanjali Sastri and many others also took up opinions which were different from what was taken up by the Union Government at that time.

I do not have the time to go into the other irregularities, but I must say that very good suggestions have been made in this connection. Because of lack of time, I am not going into those suggestions. But I am afraid that the university has not accepted many of the good recommendations which have been made in this report. Very good recommendations have been made regarding the selection committee. Why is it that they have not been accepted? Why is my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri so much engrossed in having the Pro-Vice-Chancellor? Does he know that the premier university of Calcutta has never had a Pro-Vice-Chancellor? Why does he say that there should be a Pro-Vice-Chancellor?

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

Shrimati Renu Chakravartty: Unfortunately, I do not have the time to go into the various recommendations. A very good recommendation has been made regarding the selection committee. There are various other good proposals which have been made, which the university has not accepted. I feel that the post of Pro-Vice-Chancellor must be abolished, because it is these Pro-Vice-Chancellors both in the Banaras Hindu University as well as here, who have been sources of trouble, and, therefore, we do not want them. Our best universities are run without Pro-Vice-Chancellors. That is the first point that I would like to emphasise, in conclusion. My second point is regarding the selection committee and the financial irregularities. All the recommendations made in this behalf should be accepted. As a matter of fact, I would say, that as a first instance, we should accept *in toto* all the recommendations made by this enquiry committee, which have been, on the whole, very good.

Mr. Deputy-Speaker: Now, let us hear Raja Mahendra Pratap. Otherwise, everybody else will be interfered with, when he speaks.

राजा महेन्द्र प्रताप : जनाब मन, मुझे कुछ खास हक है इस मामले पर बोलने का मैं वैसे तो बड़े ही कट्टर वष्णव घर में पैदा हुआ, मगर मेरी सारी तालीम ए० बी० से ले कर बी० ए० तक इसी मदरसे में हुई है । इस का नाम अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी है पहले इस का नाम एम० ए० ओ० कालिज था । मैं जैसा भी हूँ, भला हूं या बुरा हूं इसी मदरसे की तालीम का नतीजा हूं ।

Shri Goray: Then something is wrong with that university.

राजा हेन्द्र प्रताप : ओल्ड बाइज का भी म मेम्बर हूं और कोर्ट का भी मैम्बर हूं । मुझे यह देख कर बड़ी तकलीफ हुई कि आज मेरे मेहरबान, मेरे साथ बैठने वाले पंडित, श्री प्रकाशवीर जी ने इतने भाव, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दुर्भाव से इतनी बुराइयां हमारी इस यूनिवर्सिटी की कीं । इस में एक बड़ी बात समझने की है कि यह माननीय सदस्य पैदा हुए हैं हिन्दू और ब्राह्मण परिवार में, और यह जो हमारी यूनिवर्सिटी है यह मुस्लिम यूनिवर्सिटी है । मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर इन का ऐसी बातें कहना मुल्क में हिन्दू और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर

करता है। यह बड़े अफसोस की बात है कि यहां पर इस तरह की बातें कही जाती हैं। हमारे पंडित जी को कम से कम ये बातें नहीं कहनी चाहियें थीं। अगर कोई मुसलमान या अलीगढ़ का कोई और आदमी ये बातें कहता और बुराइयां निलकता तो हम को कोई दुःख नहीं होता।

अब मैं यह एक अर्ज करूं कि यह कहा जाता है कि साहब वहांपर कम्युनिज्म है या कम्युनलिज्म है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ने कभी पूछा है कि कम्युनिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है। आप ने कभी पूछा है कि हिन्दू धर्म क्या है, इस्मलाम क्या है। क्या कभी दरयाफ्त किया है इस बात को। मैं कहता हूं कि यह सब ख्यालात हैं। आप ने कभी इस बात को दरियाफ्त नहीं किया। कुछ हालात थे कि जिन की वजह से ये ख्यालात उस वक्त पैदा हुए, बढ़ रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है इस बात पर कि एक तरफ तो हमारी सरकार, हमारे मेहरबान, मोहतरिम आनरेबल पंडित जवाहर लाल नेहरू कहते हैं कि सुलह होनी चाहिये, अमन होना चाहिये, सब मिल कर रहें, मगर इस सदन में आकर हम देखते हैं—आप मुझे ऐसा कहने के लिये माफ करेंगे कि लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

राजा महेन्द्र प्रताप : हम को लड़ना नहीं चाहिये, मिल कर रहना चाहिये। हम इस हाउस में सब एक खानदान के हैं। हम को मिल कर अपने मुल्क की तरक्की के लिये काम करना चाहिये और आपस की दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें सोचना चाहिये कि ये ख्यालात किस तरह से पैदा हुए .....

उपाध्यक्ष महोदय : इस रिपोर्ट पर भी तो आपको कुछ कहना चाहिए।

राजा महेन्द्र प्रताप : जो रिपोर्ट दी गयी है उस को तो बिल्कुल उसी तरह मान लेना चाहिये। उस के खिलाफ यहां पर कोई आवाज नहीं उठानी चाहिये। हम ने अच्छे से अच्छे आदमियों को यहां पर मुकर्रर किया था। उन्हों ने हमारे सामने रिपोर्ट पेश की। अब उस रिपोर्ट के खिलाफ कुछ कहना या अब युनिवर्सिटी के खिलाफ यहां कोई चर्चा करना इस के माने यह होते हैं कि हम उन मोहतरम रफीकों को और मेम्बरान को बुरा समझते हैं। यह नहीं होना चाहिये।

जमीन के बारे में बात उठाई गई। मैं आप को बतलाऊं कि इन्हीं ख्वाजा साहब ने इसी अलीगढ़ में ३०–३० और ३५–३५ रुपये गज पर जमीनें बेची हैं यहां पर तो उन्हों ने कुछ भी नहीं लिया। यहां बातें मालूम होनी चाहियें। मेरा कहना यह है कि बेकार ऐसी बातें नहीं लानी चाहियें और मेरा यह कहना है कि युनिवर्सिटी को इस को बिल्कुल अधिकार दे देना चाहिये कि वह अपना इंतजाम आप करे।

यह भी कुछ लोगों को ऐतराज है कि मुस्लिम युनिवर्सिटी क्यों कहा जाये और हिन्दू युनिवर्सिटी क्यों कहा जाय। मैं कहता हूं कि साहब अगर दीन, दीन है, तो दीन रहेंगे। इसलिये हिन्दू और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नामों के रखने में क्यों हर्ज है बल्कि मेरी समझ में तो बड़ा फायदा है। हम तो तमाम मुसलमानों को अफ्रीका के मोरक्को और नाइजीरिया के मुसलमानों को इस के जरिये अपना दोस्त बना सकते हैं। हमारी सरकार को इस को इस्तेमाल करना सीखना चाहिये। इसी तरह मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों के वास्ते कहूंगा कि यह कम्युनिज्म का आप के दिमाग में कुछ ख्याल भर गया है। आप ने सोचा नहीं कि यह ख्याल कैसे आप के दिमाग में आ गया? खैर जैसे भी हो वह ख्याल आपके दिमाग में आगया है और आप उसके चलाये हुए चल रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि कोई हर्ज नहीं है। हम अपने इन कम्युनिस्ट इन भाई बहिनों के द्वारा चीनी कम्युनिस्टों की दोस्ती हासिल करें और रूस कम्युनिस्टों की भी दोस्ती हासिल करें। हमें अपने मुल्क के फायदे के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए इन कम्युनिस्ट भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिये और हमें मुसलमानों को भी उसी तरीके

[राजा महेन्द्र प्रताप]

स इस्तेमाल करना चाहिये । हम अफ्रीका और वस्त ऐशिया को मुसलमानों के द्वारा अपना दोस्त बनायें । मेरा कहना यह है कि जो हालता हमारे मुल्क में हों उन को हम इस्तेमाल करना सीखें । हमारे यहां बहुत चीजें मौजूद हैं जिनका कि हम फायदा उठा सकते हैं ।

हमारे यहां यह जो मुख्तलिफ ख्यालात में आपस में लड़ोई होती है यह गलत बात है । मैं ने कितनी दफा कहा कि आप एक मुहकमा बनाइये और खयालात की परख करिये । जो ख्याल लड़ाये हमें वह बुरा और जो ख्याल हमें मिलाये वह अच्छा । इस तरीके से ख्यालात की परख की जाये चाहे वे मजहब में ही चाहे वे पार्टी में हो । अलबत्ता जो ख्याल हमें लड़ाये वह बुरा है । मैं कहता हूं कि पार्टियां रहें, दीन रहें . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें ।

राजा महेन्द्र प्रताप : बस मैं खत्म ही कर रहा हूं । मेरा कहना यह है कि हम अपने आदमियों को अच्छा बनायें । मैं तो अपने मुसलमान भाइयों को कहूंगा कि वे अपने मुसलमान भाइयों को अच्छा बनायें और इंसान बनायें । उसी तरीके से अपने हिन्दू भाइयों को कहूंगा कि आप हिन्दुओं को अच्छा हिन्दू बनाइये और इंसान बनाइये । ऐसे पूजा, पाठ, रोजा नमाज और कीर्तन करने से क्या फायदा हुआ अगर हम इंसान नहीं बने और बेईमान रहे ? अगर हम इंसान नहीं बनते और नेक नहीं बनते तो फिर यह आप का पूजा पाठ करना, रोजा रखना या नमाज पढ़ना और कीर्तन करना कोई माने नहीं रखता और यह सब ढोंग हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने कह लिया । बस अब तो खत्म ही कर दीजिये ।

राजा महेन्द्र प्रताप : उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप मेहरबानी कर के तशरीफ रखें । मैं ने दूसरे मेम्बर साहब को बुला लिया है ।

Shri Balraj Madhok: We have just now heard two very interesting speeches, and a very imaginative flight on the part of our hon. friend, Raja Mahendra Pratap. Maulana Hifzur Rahman Sahib and Shrimati Renu Chakravartty have both pleaded that there is no communalism and no communism in the Aligarh University. May be true. But the question that is before us just now is the Report of the Aligarh Muslim University Inquiry Committee.

In this very House a decision was taken that some inquiry should be held. The House was of the opinion that a Visitor's Committee should go there. But then the Vice-Chancellor somehow prevailed upon the Education Minister that a Committee appointed by the Executive Committee would perform the same functions as that of a Visitor's Committee and that there would be no interference with its working. The hon. Minister of Education also gave an assurance in this House that there would be no interference with its work, that the Vice-Chancellor would not sit on the Committee and that this Inquiry Committee would perform the same functions in the same impartial and independent way as a Visitor's Committee could.

But then what do we find in this Committee's Report. In the first place, this Committee had orginally four members. Later two more were added, both from the same place. They come from Kashmir. I also happen to come from Kashmir. As regards the *bona fides* and outlook of these members—at least about one of them—it is better not to say much, because I know more and I do not like to refer to personal things here.

Even after that, when the Committee met, the Vice-Chancellor decided that he must be there, and because he was there, many of the intending witnesses would not come. It is on record—reports were given to the

police—that those who wanted to give evidence were threatened; some were even manhandled. One of them Dr. Rastogi who inspite of threats had the courage to give a memorandum to the Committee and to appear before it. He was dismissed. Similar things happened with others. When there was such an atmosphere of terror, how could anybody come forward to tender evidence before the Committee? This very fact vitiated the whole atmosphere in which the Committee was to work and that alone is enough to reject the findings of this Committee, because the full fact could not come before it in the circumstances in which it was placed.

Then the terms of reference of this Committee as given in the Report pertain to financial irregularities and to admission of students. I agree with Shrimati Renu Charkravartty that there are financial irregularities and nepotism in other departments and other universities also. But the real charge against the Aligarh University is not on the score of financial irregularities, though that too in itself is a serious charge, because it is public money which is being spent there; it is being run on grants given by the Government of India and the Government of India's money is public money. So that also is a very important aspect which we cannot simply brush aside. But the real charge, which was not mentioned in the terms of reference and which, in fact, should have been the only term of reference is concerning the communal and anti-national character of the University.

Now, some friends say that this term 'communalism' can be used by anybody to dub the other. We know what is communalism. My hon. frined, Maulana Hifzur Rahman asked: how many Muslims are there in Banaras Hindu University? I ask: why raise the question of Hindu and Muslim? The question is: here is a University which is an Indian University. The Aligarh University and the Banaras University are both Indian Universities run with Indian Indian money for the Indian people. In the matter of appointment or admission, why should the question of Hindu or Muslim be brought in?

Shri Jamal Khwaja (Aligarh): On a point of information. This question was raised by Shri Prakash Vir Shastri.

Mr. Deputy-Speaker: He is going to have his opportunity.

13.39 hrs.

[SHRI JAGANNATHA RAO *in the Chair*]

Shri Balraj Madhok: Let there be advertisement; let people apply for jobs and let there be selection based on merit. He may be a Muslim, Sanatanist, Jain, Sikh or Christian. If a Muslim is selected simply because he is a Muslim, even though he has lower qualifications than the other applicants, that is communalism. If in the same way some Muslims apply for jobs in Banaras University and if that University does not take them simply because they are Muslims, and instead takes non-Muslims, even though they have lower qualifications that again would be communalism. Both are equally condemnable. I challenge Shri M. H. Rahman to point out a single case where this thing happened in the Banaras University. How many Muslims applied for jobs in the Banaras University and were rejected simply because they were Muslims? On the other hand, in the case of the Aligarh University, there are dozens of cases where better qualified Hindus applied, and were not taken simply because they were Hindus. This is communalism. If you can point out a single instance where a Muslim applied and was not taken though he was qualified, we will condemn it as strongly as we condemn this in the case of the Aligarh University.

The real question is not whether the applicant is Hindu and Muslim. After all, there are certain criteria. What is nationalism? What is secularism? Smt. Renu Chakravartty says that Communists are secular. It is not whether you believe in God

[Shri Balraj Madhok]

or not. It means only this, that you do not make a distinction between one citizen and another of India on the basis of caste and creed. If you make that distinction, it is communalism. I say the Jana Sangh is a better secular party than the Communist or the Congress Party. The Congress Party is encouraging communalism by its policies. Let it not make distinction between persons on the basis of religion.

In the matter of admission we find that the qualifications for Muslim boys are lower and for non-Muslims higher. Whatever criteria you lay down, whether it be 60 per cent marks or first class, should be uniformly applied. If under that criteria all those admitted happen to be Muslims, nobody should have any objection. But when you say there should be one criterion for the Muslims and another for the others, it becomes communalism. This is going on. I challenge anybody to say it is not so. The facts are there.

There is something much more serious. Just now the hon. lady Member read out something from the Aligarh University Magazine. They still talk of a separate Muslim nation. The two nation theory was born and cherished in the Aligarh University. They say they have a separate culture. When you have a separate culture, separate language, separate history, then you are a separate nation. It is this talk of a separate nation, separate culture and separate history which goes against Indian nationalism.

In this country there are people of all religions. People worship in temples, gurdwaras, mosques or churches freely. According to the basic Indian culture, from the times of the Rig Veda, there has been freedom to every one in the matter of worship.

स एको सद्, विप्रा बहुनां वदन्ति

That is, God is one; He can be worshipped and called in many ways. Therefore, we have no objection if anybody goes to the mosque or the church, but the question is: can you, on that basis, claim to be a separate nation? There are people who idolise Mohd. Ghori and other foreign invaders. Suppose I am Christian, and I say the foreign rulers were Christians, and those who were fighting against them for freedom were Hindus, and therefore those foreigners who were Christians were my heroes, and the others are kafirs, then I am a traitor to this country. Before the Christian invaders came to this country, the Muslims came,—Babar, Ghaznavi, Kasim etc. If an Indian Muslim thinks that simply because these foreign invaders happened to be Muslims, they are his heroes and the great Indians who fought them like Jai Pal, Anang Pal, Rana Sanga etc., were kafirs, that is communalism. This is negation of secularism and this is the thing which is creating trouble in this country. It is this philosophy which is being kept alive in the Aligarh University, and it is a danger to Indian unity. Therefore, I want you to look at the problem not from the Hindu-Muslim angle, but from the national angle.

So, the greatest danger to our national unity is this problem of separatism that is growing in the name of caste, community and religion. My sister said that India had rejected the two-nation theory. We may have rejected it, but here are people who have not. People in the Muslim Convention calling themselves nationalists is a cruel farce.

Shrimati Renu Chakravartty: I said there were some people, but to condemn an entire people and a university is not proper. There are nationalists like Dr. Syed Mahmud who do not believe in the two-nation theory.

Shri Balraj Madhok: There may be exceptions, but I say that by and large the Aligarh University still continues to be the centre of that very mentality which resulted in the partition of this country. We are not

against any individual, a particular persion or professor, but against that mentality. So long as that mentality continues, we will continue to raise our voice against this University, because we think it continues to be a plague spot in India. Until and unless this plague spot is cleared of its plague symptoms and made a national organisation, there will be danger. Let the professors be all Muslim, let the students be all Muslim, but let nationalism be taught there. This Committee was not supposed to go into these matters, but there are so many complaints that people there have indulged in activities which are pure and simple anti-national. When something happens in Pakistan, when a Pakistan team wins, people rejoice there. It is difficult to imagine how any Indian national can think of it or behave like that, but that is happening. It is this aspect which should be condemned.

There is a reference to the Banaras University and that non-vegetarians are not admitted to the hostels. But this Enquiry Committee was not meant for that University. In fact, my charge is that there is discrimination. For the Banaras University you had a Visitor's Committee, but not for this University. I demand there must be a Visitor's Committee. And this Committee had no business to go into Banaras University matters and say what is happening there.

There are so many other things to be said about discrimination, appointments, financial irregularities etc, but I come back to the basic problem. Unless and until the anti-national and communal character of this University is changed, it will have to be criticised in this House and outside also.

Shri Jamal Khwaja: Last year, in February or March, the hon. Member Shri Prakash Vir Shastri raised a half-hour discussion in which he made, I think, 17 allegations, very serious allegations, which involved eminent persons like the Vice Chancellor of the Central University, members of the staff and other distinguished persons. I made an offer that day, and I said: let an honest and impartial body of persons be appointed to go into the matter. Regarding one particular allegation, I said that if that was proved to be true, I would resign. I did not say this in anger, but out of a sense of justice.

After that, I wrote a personal letter to Shri Prakash Vir Shastri, repeating the offer that I had made in this House, but I am sorry to say that that letter was not even acknowledged by him, although we are both colleagues, Members of the same Lok Sabha. I expected that he would have the courtesy, the decency, at least to acknowledge that letter. Anyhow, I know that letter reached him because I actually put this question to him in the presence of a very distinguished colleague of mine here, and he said that that letter had reached him.

After almost a year, the report of the Enquiry Committee is here. They have gone into all those charges and allegations, and each one of those charges has been proved to be either wrong or absolutely baseless, each one of those 17 charges which were levelled by Shri Prakash Vir Shastri in this House. Because technically it was not a Visitor's Committee but only a University Enquiry Committee, because two Members were added to the list, to insinuate that they did not perform their functions honestly and independently, to say, as one hon. Member did, that he would not like to say anything about the gentleman who comes from Kashmir because the less said about him the better, is most undignified. I wonder what is happening to our public morality, to our decency. Is this the way the Members of Parliament should function? I should have thought that after the committee had given its verdict, the hon. Member would have had the decency, if not to apologise, at least to express his regret that he had been misled. Far from

[Shri Jamal Khwaja]

that, the same hon. Member again repeats those charges. I cannot understand what has happened to him. Although from the very beginning, when he had come to this House and had become one of us, I did not agree with many of his views, I always respected him and I thought that he was sincere. I do not know. I still think that he is sincere. But I cannot understand the mechanism or the way his mind works. He does not represent only himself; he is symbolic of the mentality in India which is a most painful and dangerous trend for India. Distinguished and eminent persons are appointed and they submit a report after a great deal of study and a good deal of expenditure and then insinuations are made against their honesty. He said an atmosphere of terror was created and people were prevented from giving evidence. These are baseless charges that are being made. The House will remember that Shri Vajpayee made an allegation against the Vice Chancellor of the University. When I asked him whether he understood what he was saying, he said he understood it. I pointed out the name of the paper which had published an unqualified apology for the remarks that had been printed in that paper. I am sorry to say that the hon. Member said that the apology concerned another matter. But the fact is that the apology was specifically concerned with the very matter in issue. It is his own paper published by his own party. This is not fair . Let us not lower the standards of morality. Let there be differences of opinion; I can understand them.

I have myself condemned certain things in the most unqualified way, not now but ever since I had the capacity of independent judgement. There are people who take the name of secularism and claim themselves to be secular. We also condemn the two-nation theory. Fortunately or unfortunately I belong to that section of thought since my very childhood which was steeped in the traditions of nationalism. At the risk of danger to life and property, there was a small group in Aligarh which upheld the traditions of nationalism and condemned the two nation theory. Let not people think, as Shrimati Renu Chakravartty has said, that nationalism and secularism are the prerogative of people like Shri Shastri. There are not one but several others and among them Muslims also. We are proud of the role which the Indian Muslims have played in the freedom struggle of India; it is yet to be written. I am sure a large number of names will come up, names of people who sacrificed for the cause of the Indian freedom and whose dedication to genuine nationlism is not less than anybody else's. What I was saying was that this mentality of doubting the integrity, the intentions and motives of eminent and responsible people is a very dangerous mentality.

There are many things which Shri Shastri said. For instance, he said that the Vice Chancellor was a member and he attended those meetings. Personally I think it was not necessary. But even if he attended the meetings, he was not present at the deliberative stages, and at the time when the report was written. If Shri Shastri goes through the report, he will find that the committee has not spared the Vice-Chancellor or the others. The Committee have freely expressed their views and they have stated that after the initial misunderstanding was over they received the greatest possible co-operation and help from all concerned and they say they are grateful to the university. Secondly, the Committee invited the people who were interested in and who were spposed to know the affairs of the University to send written statements and a large number of them were sent. Even anonymous complaints were sent and the committee took full note of even those anonymous statements. In view of all these things, the attitude taken by my hon. friend is most undesirable. There are so many things. I do not know how much time I have taken.

Mr. Chairman: He has taken ten minutes. He may have two more minutes.

Shri Jamal Khwaja: What has the Mover of this debate done? Instead of going carefully into the report of the enquiry committee and the terms of reference and honestly expressing his opinion on the recommendations that have been made by the committee, he went into some new charges forgetting that all the 17 allegations he had made had been completely disproved. After that he had gain repeated those same charges. Shri Madhok.

Shri A. M. Tariq: He is gone.

Shri Jamal Khwaja: But his mentality is represented here. He said a good deal about the two nation theory. We all condemned the two-nation theory, not now but for the last twenty years or more. He also defined the concept of communalism, with which I agree. The point is how far that communalism is prevalent in Aligarh. It is a descriptive and factual problem; it is not an analytical or ideological problem. Here I must say that what is required is the objectively of judgment. We must not be swayed by passion. Unfortunately hon. Members like Shri Madhok and others are unable to look at things objectively because they are swayed by passion. There are different points of view. For instance, there is a specifically communist point of view; then there is the Jan Sangh point of view.

An Hon. Member: Jan Sangh has no view.

Shri Jamal Khwaja: There are other factors. Now, supposing three candidates applied for a job and the best of them happens to be a member of the Jamiat Islami or the communist party or some other, and if he is selected for that post, would it be right to say that the university is helping the spread of communism or communalism. What happens is the supporters and well-wishers of the candidates who are not selected start making this propaganda. This is very natural and this happens not only in Aligarh. It happens everywhere. It is human frailty. There are very few persons who can look at things objectively. This complicates the issues and makes objective judgment difficult. Shri Bal Raj Madhok said that there are different criteria for the admission of students, as between Muslim students and non-Muslim students. It is absolutely—100 per cent—wrong. There is only one criterion. Let him go into the report and study it. The university has made a distinction between internal students and external students. The internal students are those who have passed out from the institutions of the university like the various colleges like the intermediate colleges or whatever it is. The external students are those who come from outside. This distinction is made by all universities. It is made by the Oxford and Cambridge universities also. It is made by other universities in India. The Committee of Enquiry has accepted this difference between the internal and external students. The Enquiry Committee also says preference must be given. I am, therefore, surprised at the ignorance which has been shown by hon. Members about the matter of admission.

14 hrs.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Jamal Khwaja: I shall conclude. Shri Bal Raj Madhok pointed out that there is the old mentality of a two-nation theory or the Pakistan mentality which still remains. Well, let us face the facts. Yes, Sir, it remains not only in Aligarh but everywhere, and it remains not only among the Muslims but also among the Hindus and among others. What is the way out? Can we solve that

[Shri Jamal Khwaja]

problem and remove that mentality by the type of speeches that are delivered by Shri Prakash Vir Shastri and others today? Is this the way to remove that mentality? We must realise—and the House knows—that we are a democratic country, and there is no question of forcing anything. I differ hundred per cent from the ideology of the Jamiat-i-Islami, and yet recently, a member of the Jamiat-i-Islami was appointed to a lecturership in the Aligarh University. And I say, as John Stuart Mill did, "I entirely disagree with what you say. But I am prepared to give my life to defend your right to say so."

The point is this. I know what has happened. Anonymous letters were sent to the Home Ministry that Muslim communalism is rampant in Aligarh, and this was cited as an example. What is the logic of it? Where are we going? If, for instance, a brilliant scholar, who was fit for it, was appointed there—and if he happened to be a Communist—we start saying that Communists are patronised and are shown patronage. Where should we go if it is said so? Then only members of the Congress Party, the PSP and perhaps the Socialist Party would remain. The Jan Sangh has no future. (*Interruption*). So, what is the logic of all this?

Mr. Chairman: The hon. Member must conclude.

Shri Jamal Khwaja: I shall conclude. One should be honest and objective. And let us all, Members of this House, try to remove this mentality, this very undesirable mentality, and let us all try to help the people in Aligarh, the students and the staff of Aligarh, to set an example of emotional integration for the rest of the country to follow. I am confident that Aligarh would take the lead and show the example for all universities and even for the State and for the whole Union of India as such.

Shri Hem Barua (Gauhati): Mr. Chairman, Sir, I have gone through the report of the Enquiry Committee into Aligarh University affairs with great care and caution. The very idea that an enquiry committee had to be appointed to enquire into the affairs of a university is revolting. There was an enquiry committee, namely, the Mudaliar Committee, to enquire into the affairs of the Banaras Hindu University, and here is another enquiry committee appointed to enquire into the affairs of the Aligarh Muslim University. The very idea is revolting in a sense, because the universities are supposed to be the citadels of light in our country and the state of affairs in the universities must be ideal. The very idea that in our country there exist a Hindu University at Banaras and a Muslim University at Aligarh is an anachronism in the democratic set-up of our country. For psychological reasons that existed in the past, I could understand such an anachronism, but to allow such a thing to continue in the present day is a thing that passes my comprehension.

In fact, this appellation, Hindu and Muslim, must be wiped away or else there would be no emotional integration in this country. This prefix of Hindu and Muslim to the universities at Banaras and Aligarh must be wiped away at all costs. Or else there would not be any progress in this country. Today, we are speaking of emotional integration, but the type of speeches that we have listened to in this House does not bring any happiness or hope for us; and it is true that only the national mind is reflected in the speeches and at the same time the national mind is reflected in the working of the universities also. That is why, most of the universities, whether it is Banaras or Aligarh, have become hotbeds of corrupt practices. I can substantiate what I have said from this report.

What is a university in a sense? If knowledge is power, then I would say that a university is the very powerhouse of knowledge, and that is because of it that the university must

radiate a refulgence of light so that the nation might bask in that refulgence of light and progress. But the state of affairs now prevailing in our universities is rotten to the very core. As I read this report, I come across so many financial irregularities and certain other irregularities that my blood boils. Excuse me for saying that. The nation is heading towards disruption—to corruption, to corrupt practices, to anomalies and irregularities. The universities are supposed to be the salt of our tiny earth, but if you drain savour out of salt, wherewith will it be salted? That's what has happened.

I have gone through the report and I find that it is a fair appraisal of the state of affairs obtaining in this university, and gives an indication of the state of affairs prevailing in some other universities also. I would say that it is better to enquire into the working of all these universities, to institute a committee to enquire into the working of the different universities and that would reveal facts that will be shocking like the facts as revealed by this report under consideration.

Whenever I think of the Aligarh University, I think of its past, with its rich traditions, its intellectual attainments, its idealism, etc. They loom large before my eyes. But when I read about the university as revealed in this report, that picture of high traditions, of a great cultural age, of idealism, etc., gets shattered and demolished. That is what has happened. I cannot believe that our public institutions—I do not say particularly about the Aligarh University—or most of these public institutions have lost their values and their ideals. But now it has come to that, and they reflect the atmosphere in the country. This is an age of lost values in our country. We do not have regard for high morals or high standards; there is an absence of regard altogether for high morals and values. That is being reflected in the working of the universities also.

If I can say so, this university has revealed such things as mentioned in the report. I do not care whether it is a Muslim or a Hindu university. I never work on prejudices. I do not work on communal ideals or whatever that might be. The fact is, this is a public institution of our country. When we go through the report, we will find that the state of affairs in this public institution is shocking. May I say that there is embezzlement of funds in this university, loss of public property and loss of funds? There is defalcation and misappropriation. While I mention misappropriation and defalcation, some people might think that I am only singing an outworn tale or an outworn song. I might be wrong, but in order to substantiate what I have said, may I read the irregularities from the report itself?

Herein, you find the remarks of the Accountant-General of Uttar Pradesh, and he says startling things. As I read them, really speaking, my blood started boiling. At page 49 this is what is said:

> "We have examined this report. The alleged irregularities were of a serious character and related to almost every aspect of financial management in the university. The more serious audit objections related to embezzlement and misappropriation of funds; defalcation and tampering with the records; unauthorised revision of estimates in respect of sanctions by Government; complete mismanagement of large construction projects; improper maintenance of records and non-observance of financial procedures; and inefficient and tardy collection of dues from students."

A sparrow whispers into my ears that all this has been squared up, but I can prove that these irregularities were pointed to the university authorities and the report says that the university authorities did not try to stabilise or put the records straight, and

[Shri Hem Barua]

nothing was done in the direction till the Enquiry Committee was instituted. What do they think of themselves? I think they have the rhino's hide to blanket their body and to blanket their conscience as well. I do not know whether rhinos are available in U.P., but I know they are available in the State from where I come. They have allowed their conscience to be blanketed.

When these irregularities were pointed out to the authorities, till this enquiry committee was instituted, nothing was done. This is a rotten history of irregularities and I would accuse Dr. Shrimali and his Education Ministry for allowing this state of things and financial irregularities to continue for such a long period of time. The enquiry should have been instituted much earlier. The report conclusively proves that there is something wrong in the State of Denmark, that there is something wrong in the university.

I do not bother who are the persons connected with it. I never work on prejudices, but I would say a hundred times whoever might be associated with this sort of administration, which is rotten, the administration that is charged with embezzlement of funds and with financial irregularities and so many corrupt practices, that administration does not have the moral right to exist even for a moment. I will say a hundred times that those persons —I have never seen even their shadows—who are responsible for this sort of administration are a disgrace in a temple of learning, whoever they might be. Everything has gone wrong.

What about the medical college? The people are so high-minded that whenever there was a call for a medical college, they gave subscriptions liberally. My information is—I say from the record—that about Rs. 44 lakhs were collected as public donation and the pity is, you would be astonished to hear that no record could be produced. Besides, Rs. 5 lakhs are put down as irrecoverable amount. Rs. 13 lakhs could not be accounted for. The people are bleeding to pay for education; it is all poor people's revenue and the Central Government is giving grants also. I ask, what moral right does the administration have to waste Rs. 13 lakhs like that and Rs. 5 lakhs on another occasion? I feel this university has turned into a slaughter house of all morals and ethics and high instincts of life. I know I am using strong words, but that is how I feel about it. This is not the only university. There are other universities also. When we discussed the Banaras Hindu University, I had the same feeling. University administration have lost their character; students have lost their character also. Administrators behaving in this sort of way is most astonishing.

There is nepotism also in the matter of appointment. Why should there be nepotism? These are the people who go about criticising the Congress Government in the country and the Congressmen. If I am not morally pure, I do not have the right to criticise anybody. I will never criticise a man unless I am morally pure and right. These are the people—the teachers and people in charge of public institutions —who go about running down our national leaders. Do they have the moral right to go about doing like that, if they cannot prove themselves to be the epitomes of culture, fineness and nobility?

In matters of appointment, why should there be any nepotism? I am also connected with an educational institution and I always see that there is no criticism against my appointments, because I always see to the fact that the best man is appointed. The teachers are the people in charge of the destiny of our future generations. If they are not intellectually well-equipped, they will lead our young men and women to the ditch. The report points out that here certain persons were appointed without any

selection board, without any advertisement and without any interview. I do not want to say anything about the credentials of the persons appointed like that, but the very fact that people were appointed without any advertisement, without any selection board or interview is a reflection on the university. There is reference to the Tibbiya College in the report. There is an attempt to shield it, but I can point out from the report that there are very adverse remarks against this college. The report says that some of the old boys of the college came, saw us and presented a memorandum to us. Certain serious allegations were made against the authorities. The Vice-Chancellor was present when the allegations were made and none could be refuted. Therefore, to try to shield this would be wrong.

What about the Vice-Chancellor? I have not seen the shadow of that gentleman, but here is a Vice-Chancellor who uses his emergency powers like anything. The report says that he used his emergency powers as many as 135 times, out of which the use of emergency powers on 52 occasions was totally unwarranted. What was the Executive Council doing? The Executive Council constitutes the authority of the university. Excuse me for saying that the Executive Council of this university is only a rubber-stamp; it dittos what the Vice-Chancellor says or does. This Executive Council is expert in writing off amounts that could not be accounted for. The report says by one resolution it wrote off Rs. 78,179.

So, the Executive Council does not function properly. The administration does not function properly. Naturally enough, the university reflects its own character. We wanted light from the university, but the university is radiating only darkness. With darkness, there is poison also and I am afraid that poison might vitiate the atmosphere of the whole country.

Shri Ansar Harvani: The other day while speaking on the Banaras Hindu University, I remarked—I now take the liberty of repeating it—that I consider the Banaras Hindu University and the Aligarh Mulim University as two eyes of Mother India. If one eye is disfigured, Mother India becomes one-eyed; if both eyes are disfigured, Mother India becomes blind.

Some Hon. Members: What about other universities?

Shri Ansar Harvani: They are not central universities.

Therefore, I feel that it is the duty of every man and woman in this country to take interest in the affairs of this university. It is not only for the Muslims of India to take interest in the affairs of the Aligarh Muslim University and it is not only for the Hindus to take interest in the affairs of Banaras Hindu Univevrsity. So, I congratulate the various sections of the House for taking interest in the affairs of this university and I express my gratefulness to them on behalf of those who have been associated with this university for the last 20 years.

My friend, Shri Prakash Vir Shastri, took great interest in the university. I hoped and prayed that he would take genuine interest. But the cat was out of the bag the moment he declared, while concluding his speech, that the Government should make a probe into the affairs of the university and the history department of the university is being used for anti-Indian activities for searching maps of Chinese border and for helping the Chinese on that side. That shows his intention of his interest in the university. He belongs to that group of gentlemen—I call them gentlemen by courtesy only—who are suspicious of everything with which the Muslims are associated, who always suspect the good intentions of the Muslims, who always suspect the patriotism of the Muslims. I want to remind him, Sir, that Aligarh University is that university which has

[Shri Ansar Harvani]

produced some of the greatest patriots. I know that it is not relevant to this report, but I want to remind him that even today, in the far off Pakistan, that undaunted soldier of India's freedom, Khan Abdul Gaffar Khan who is languishing behind prison bars and he was produced by the Aligarh University. I want to remind that hundreds of young men from Aligarh University courted imprisonment for India's freedom. If they had not that patriotism they would not have gone to jail. In future also, Sir, boys and girls of this University will work for the reconstruction of this country and make it a great country of which the world can be proud of.

Sir, great exception has been taken about the attendance of the Vice Chancellor at the various committee meetings. If we go through the report we find that he did attend the meetings. But it is the custom that every enquiry committee metting is to be attended by at least one representative of the organisation about whom the enquiry is being made. But it is wrong to say that he in any way influenced the witnesses or in any way intimidated those people who came there. If we go through the report we will find that even written memoranda were accepted by the committee and were considered. The poor Vice Chancellor had no access to those written memoranda. What to say of written memoranda, even anonymous rpresentations were accepted by the Committee—the report itself points it out and the Vice Chancellor had no access to those anonymous representations. Then, we should not forget that when the Committee met and deliberated the Vice-Chancellor was not present there. We should not forget that when the Committee prepared the report and adopted it the Vice Chancellor was not present. We also should not forget that the Aligarh University teachers are brave people, educated people and they ought not to have been afraid of the Vice Chancellor. The Vice Chancellor's powers are not so wide that he could have victimised them even if they had given an adverse report about the university. Apart from that, we know very well that one of the university teachers, with whom my hon. friend seems to be very friendly, made a very damaging report and still he cotinues to be the chairman of the chemistry department of the university and no action has been taken against him. He was given full freedom to express his opinion before the committee. That is one example. It will convince you and the House that the Vice Chancellor in no way exerted his influence.

Then, it has become a fashion with some hon. friends to make wide allegations against the Aligarh University. A number of hon. friends have pointed out that the allegations made by my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri last time during the half-an-hour discussion have been debunked by this report. The purchase of a house was referred to. They have pointed out that the university has paid less cost for the house than it deserved.

Reference has been made about appointments. Maulana Sahib pointed out in his reply that 1250 appointments were made and out of that only 11 were considered to be irregular. May I know about the appointments made by the Home Ministry of our Government? May I know about the appointments made by the Ministry of Information and Broadcasting? May I know about the appointments made in the various Ministries? What is the percentage of appointments to which the Union Public Service Commission takes exception (*Interruption*)? I say, Sir, with full responsibility that the record of appointment of teachers in the Aligarh University has been much better than in any State Government in this Country or in the Central Government itself. Therefore, to accuse the Aligarh University for having bungled in appointments is preposterous and wrong.

He referred to admission. It has been said that the Muslim students

are being given preference there, all sorts of Muslim students are admitted and Hindu students and students belonging to other communities are not given an opportuity. I may tell you, Sir, that even before partition, even in those dark days when the Muslim League was looming large on the horizon of this country, Aligarh University was the one university which used to admit a substantial number of Hindu students on its rolls. Even in the early stages when the great founder Syed Ahmed Khan founded the university we used to have non-Muslim teachers on the roll. We know that Professor Chakravartty, whose arithmetic is even today taught to school students, was a professor in the Aligarh University as early as 40 or 50 years ago. We still remember it. I remember it with pride that when I was there 20 or 22 years ago, I used to have some of the most brilliant students as my colleagues in that university, and even today as it was pointed out, almost 30 to 35 per cent are non-Muslim students. A substantial number of of Hindu and non-Muslim teachers is there. Therefore, to say about discrimination is to repeat a lie, to repeat a policy which they have learnt at the feet of Adolf Hitler, that is, keep on repeating a lie so that people may believe it.

Sir, I was pointing out about admissions. The report points out;

> "Provided certain basic standards are maintained, there appears to be no reason why the University within those limits should for purposes of admissions to post-graduate courses, not be allowed to prefer its First Class and Second Class students...."

This is being done in almost every university. This is nothing new. If I pass my B.A. in any university, I get preference in the matter of admission to post-graduate classes in that university. This is nothing new. Therefore, why object to it.

The various aspects of the report have already been touched. I should about the post of pro-Vice-Cancellor. Executive Council of the University has not accepted all the recommendations. Reference has been made about the post of pro-Vice-Chancellor. In this connection I can give my own personal opinion. I feel that the post of pro-Vice-Chancellor in any university, whether it is the Banaras Hindu University or the Aligarh Muslim University, is not necessary. This post was created in the Banaras Hindu University in those days when a great man like Pandit Madan Mohan Malaviya was the Vice Chancellor of that University. His hands were too full, not only with the affairs of the University but also with the affairs of the country. He used to be a great Congress leader. He used to be a great Hindu Mahasabha leader. He used to be a great politician. Whatever time he could spare after attending to all these duties he devoted to the affairs of the University. Therefore, he was given a pro-Vice-Chancellor. In the Aligarh University also there used to be certain Vice Chancellors who could not give their whole time to the university affairs and they also used to be given pro-Vice-Chancellors. But today, when we are going to have whole-time Vice-Chancellors for both these two universities, the post of pro-Vice-Chancellor should be abolished. The Aligarh University has taken the plea that since the Banaras Hindu University Bill has provided for the post of a pro-Vice-Chancellor that university also wants to retain it. But they should know that the Bill has not yet been passed by this House and I know it very well that this House will stoutly and strongly resist that clause and the hon. Minister may withdraw that clause.

Therefore, Sir, I hope and trust that the University will accept all the recommendations of this Report.

श्री अ० मु० तारिक : जनाब चेयरमैन साहब, जहां तक श्री प्रकाश वीर शास्त्री के मोशन का ताल्लुक है, जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं, वह यकीनन इस लिहाज से बेहतर है कि उन्हीं ने इस मुल्क की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में तहकीक का मुतालिबा किया, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस अन्दाज से और जिन जजबात के तहत उन्हों ने इस मोशन पर और इस से कब्ल पिछले सेशन में तकरीर की, उन से जाहिर होता है कि उन का इरादा यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी के नज्मो-नस्क को बेहतर बनाया जाये और यूनिवर्सिटी की खराबियों को दूर किया जाये, बल्कि जाहिर यह होता है कि एक इन्तकामी जज्बे के तहत वह यूनिवर्सिटी के मामलात को और पेचीदा बनाना चाहते हैं। मैं उन लोगों में से हूं, जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जहां तक हमारी यूनिवर्सिटीज का ताल्लुक है, हमारे तालीमी मराकज का ताल्लुक है, हमें मजाहब से अलग हो कर उन की देख-भाल करनी चाहिये। चूंकि मेरे लिये यह इन्तहाई जरूरी है और इस को मैं निहायत अहम समझता हूं कि हम इस मसले को इस अन्दाज से देखें कि अगर एक यूनिवर्सिटी ने माली या तालीमी मामलों में या दाखलों के बारे में कोई नाजायज हरकतें की हैं, तो यकीनन मेरा फर्ज है कि मैं मुतालिबा करूं कि इस ऐवान से, एडूकेशन मिनिस्ट्री से, तमाम जिम्मेदार लोगों से, जिन पर इस की जिम्मेदारी है, कि ऐसी बातों की तहकीकात होनी चाहिये। इस के लिये किसी मजहब को या किसी कौम के नुमाइंदा होने की जरूरत नहीं है। एक हिन्दुस्तानी होने की हैसियत से यह मेरा फर्ज है कि मैं तमाम तालीमी खादमीन से मुतालिबा करूं कि अगर वहां इस किस्म की बदनजमियां हैं, तो उन को दूर किया जाये। जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी के उन लोगों को जो इस से मुताल्लिका हैं, मान लेना चाहिये और जो गलतियां हैं, उन को उन्हें दूर करना चाहिये। अगर वाकई में वहां ऐसी चीज हुई हैं तो उन को दूर करने की इतिहाई जरूरत है। अगर वे नहीं हुई हैं तो इस रिपोर्ट ने जो सिफारिशात की हैं, उन पर उन्हें पूरी तरह से अमल करना चाहिये।

आज की अपनी तकरीर में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने दो एक बातों का जिक्र किया है, जिन का मैं जवाब देना चाहता हूं। शायद श्री प्रकाशवीर शास्त्री प्रोफैसर हबीब की बात से वाकिफ नहीं हैं। उन को मालूम होना चाहिये कि प्रोफैसर हबीब इस मुल्क के एक माहिर तालीम हैं। वह इस मुल्क के एक बड़े मुवरिख ही नहीं हैं बल्कि एक बहुत बड़े वतन परस्त भी हैं। उन के किरदार से हम सब वाकिफ हैं और उन के अमल को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। शायद शास्त्री जी को हमारी सियासत का वह जमाना याद नहीं जब अलीगढ़ में मुस्लिम लीग और इस किस्म के दूसरे फिरकापरस्त अनासर का गलबा हुआ। प्रोफैसर वही थे जिन्हों ने अपने चन्द साथियों के साथ इस का मुकाबला किया। प्रोफैसर हबीब उन तमाम जलसों के लिये जिम्मेदार थे, जिन को अलीगढ़ में पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसी अजीमउलशान शख्सियतों ने खिताब किया था।

उन की किताब का उन्होंने तजकिरा किया है। मैं समझता हूं शायद उन्हों ने उन की उस किताब को नहीं देखा है। १९५१ की सैकिंड एडीशन यह है। जहां तक मुझे याद है प्रोफैसर हबीब १९४७ और १९४८ के दरम्यान चीन गये थे और उन्होंने वहां चन्द लैक्चर किये। इस लिहाज से भी उन पर उन्होंने रकीक हमला करने की कोशिश की है कि उन्होंने माओ-त्से-तुंग का नाम क्यों लिखा। इस में कोई शक नहीं है कि इस वक्त चीन और हिन्दुस्तान के ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं जितने आज से किब्ल थे। लेकिन एक सियासी तालिब-इल्म की हैसियत से मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता और न ही श्री शास्त्री कर सकते हैं कि माओ-त्से-तुंग की जहां तक जद्दोजहद का ताल्लुक है, जहां तक उन की तरफ से की गई चीन की रहनुमाई का

ताल्लुक है या गैर-मुल्की ताकत से चीन को ग्राज़ादी दिलाने का ताल्लुक है, उन्होंने एक शानदार पार्ट ग्रदा किया है । ग्रगर एक मुवरिख ने ग्रौर एक ज़हीन ग्रादमी ने उन का नाम ले लिया तो ग्राज वह कैसे कम्युनिस्ट हो गये । उस जमाने में जब मुस्लिम लीग का दौरा था प्रोफैसर हबीब कांग्रेसी थे ग्रौर कांग्रेसी होने की वजह से कई बार उन पर हमले हुए । लेकिन ग्राज उसी प्रोफैसर हबीबको ग्राप एक गलत सियासत को कामयाब बनाने के लिये कम्युनिस्ट के नाम से बदनाम करते हैं तो वह दुरुस्त नहीं है ।

जहां तक दूसरी बातों का ताल्लुक है जिन का श्रीमती रेणु चक्रवर्ती या हेम बरुग्रा साहब ने जिक्र किया है उनकी तहकीकात होनी चाहिये । ग्रगर ७०,००० या ७५,००० रुपया किसी के नाम से ब-यके कलम काट दिया गया है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिये ग्रौर ग्राइंदा के लिए उनको वार्निंग दी जानी चाहिये ।

एक ग्रौर तज़किरा किया गया है । इसके बारे में यूनिवर्स्टी की एग्जेक्टिव के मैम्बरों को सोचना चाहिये कि जो कहा गया है कि ए० एन० ख्वाजा की जमीन चाहे कम कीमत या मुनासिबी कीमत पर या ज्यादा कीमत पर खरीदी गई है, लेकिन जब यह मसला हल हो रहा था तो उनका उस कमेटी में मौजूद होना जरूरी नहीं था । इस बारे में यकीनन ग्राइंदा के लिए यूनिवर्स्टी के खादमीन को, यूनिवर्स्टी के मामलात में दखल रखने वाले लोगों को खयाल रखना चाहिये ।

यहां यह भी कहा गया है कि वहां पर कम्युनिस्टों का ग्रसर है, वहां पर जमायत इस्लामी का ग्रसर है । मैं इन तमाम बातों में पड़ना नहीं चाहता हूं । मैं यूनिवर्स्टी के उन हज़रात से जिन के हाथ में वहां का नज्म नस्क है यह जानना चाहता हूं कि पिछले चन्द महीनों में क्या कुछ लोगों को यूनिवर्स्टी की मुलाजिमत से बेदखल किया गया है ग्रौर यह कह कर किया गया है कि वह कम्युनिस्ट हैं ? मैं इस बात को ब-हैसियत एक शहरी पसन्द नहीं करता हूं कि इस तरह की वजूहात बयान कर किसी को बेदखल किया जाये । ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना मुल्क में खास किस्म के जज़बात फैलाने के लिए दुरुस्त नहीं है । मैं जानता हूं कि मेरे ग्रजीज़ दोस्त श्री ग्रनसार हरवानी की हमशीरा को इस वास्ते बरखास्त किया गया है कि वह कम्युनिस्ट हैं लेकिन १९४७ में उन्हीं हज़रात ने लखनऊ के मुस्लिम कालेज से इस लड़की को इस लिए निकाल दिया था कि उसका भाई कांग्रेसी है । मैं ग्राप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है, कि क्या इस तरह की बातें मुल्क के लिए एक खतरा पेश नहीं करती हैं । क्या यह सही है कि ग्राज ग्राप ग्र० मु० तारिक को इसलिए कत्ल करें कि वह कांग्रेसी है ग्रौर जब ग्राप इस लिहाज़ से कत्ल कर सकें तो—कहें कि वह कम्युनिस्ट है । मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि इन तमाम बातों की पूरी तहकीक होनी चाहिये ।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रगर यूनिवर्स्टी में कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, ग्रन्दरूनी साजिशें हैं या बाहर के लोग यूनिवर्स्टी के ग्रन्दरूनी मामलात में ग्रपने सियासी मकासिद हासिल करना चाहते हैं तो मैं वजीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उसकी तरफ खास तवज्जह दी जाये ।

इस वक्त मुल्क में एक खास किस्म की तालीम की जरूरत है जिससे लोगों का जहन साफ हो ग्रौर बिला लिहाज़ मजहब ग्रौर मिल्लत के वे मुल्क की खिदमत कर सकें । मैं प्रकाशवीर शास्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि उनको इस रिपोर्ट से इत्मीनान हो जाना चाहिये था ग्रौर इत्मीनान हो जाना चाहिये था इस बात से भी कि यूनिवर्स्टी दाखिले के मामले में नाजायज़ हरकतें नहीं करती है ग्रौर उनको बहैसियत एक ग्रच्छे शहरी के इसको मान लेना चाहिये था । सारी यूनिवर्स्टी को, उसकी कुर्बानियों को उसके माज़ी को, उसके हाल को, उसके मुस्तकबिल को तारीक बनाना न दानिशमन्दी है ग्रौर न ही दयानतदारी । मैं बहैसियत एक मुसलमान श्री हरवानी की इस बात की ताईद करता हूं कि ग्रलीगढ़

[श्री अ० मु० तारिक]

यूनिवर्स्टी में जहां आप यह देखते हैं कि एक जमाने में वहां ऐसे लोगों का गलबा हुआ जो हिन्दुस्तान की तहरीके आजादी से इत्तिफाक नहीं रखते थे, वहां आपको यह भी देखना चाहिये कि उसका कयाम किन हालात में इस मुल्क में हुआ और इसको बनाने के पीछे किन का हाथ था । इसके बावजूद भी उस यूनिवर्स्टी ने मुल्क की, नैशनलिज्म की और इस मुल्क की जद्दोजहद की जो खिदमत की है, उसको एक नहीं लाखों प्रकाशवीर शास्त्री भी इस मुल्क की तारीख से हटा नहीं सकते हैं ।

मैं बलराज मधोक साहब की एक बात का भी जवाब देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि जब मुहम्मद गोरी का किस्सा आता है या मुहम्मद कासिम का किस्सा आता है तो हमारे जजबात उभर जाते है । मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता हूं । उनको सोचना चाहिये कि आज जब आप ताजमहल की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मुगल पीरियड की यह यादगार है, जब औरंगजेब का आप जिक्र करते हैं तो कहते हैं वह मुसलमान बादशाह था लेकिन जब आप अंग्रेज का जिक्र करते हैं, उसके जुल्म और सितम की बात करते हैं तो आप कभी नहीं कहते हैं यह ईसाई राज था, आप इसे ब्रिटिश गवर्नमैंट कहते हैं । इसके लिए न मुसलमान जिम्मेदार है और न ही हिन्दू जिम्मेदार है बल्कि यह एक साजिश के तहत किया गया है और उस साजिश के लिए अंग्रेज जिम्मेदार हैं । जब आप ताजमहल की बात कहें तो उसे मुगल पीरियड की यादगार कहें, जब औरंगजेब की बात हो तो उसे इस्लाम का नुमाइंदा कहें और जब अंग्रेज का नाम आये तो आप में यह जुर्रत नहीं होती है कि आप कहें कि इस मुल्क में २०० साल तक ईसाइयों की हुकूमत रही । इन चीजों को जब आप खुद इस रंग में पेश करें और फिर छोटे छोटे बच्चों के जहन में इस बात को डालें, तो इसका असर उन पर बुरा ही पड़ सकता है । उनसे आगे चल कर आप किस चीज की तवक्को कर सकते हैं ।

बहरहाल इन चीजों का अलीगढ़ यूनिवर्स्टी से कोई ताल्लुक नहीं था । मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि हुकूमत इन नुकात के बारे में और इन सिफारिशात के बारे में कुछ कदम उठाये । मैं हरवानी साहब की ताईद करता हूं कि यूनिवर्स्टी को इन बातों को मानना चाहिये ।

मैं यूनिवर्स्टी के खादिमान से एक छोटी सी और दरख्वास्त करना चाहता हूं । उनको भी वुसत कलबी का मुजाहिरा करना चाहिये । पिछली दफा एग्जेक्टिव का जब ईलैक्शन हुआ था उस वक्त उसमें कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थीं । मैं दरख्वास्त करूंगा कि आइंदा के लिए ऐसी गलतफहमियों का मौका न दिया जाये और वुसत कलबी का वे सबूत दें ।

شری ع - م طارق (جموں تتھا کشمیر) - جناب چیرمین صاحب - جہاں تک شری پرکاش ویر شاستری کے موشن کا تعلق ہے - جس پر آج ہم بحث کر رہے ہیں - وہ یقیناً اس لحاظ سے بہتر ہے کہ انہوں نے اس ملک کی ایک بہت بڑی یونیورسیٹی کے بارے میں تحقیق کا مطالبہ کیا - لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جب انداز سے اور جن جذبات کے تحت انہوں نے اس موشن پر اور اس سے قبل پچھلے سیشن میں تقریر کی - ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکا ارادہ یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے اور یونیورسیٹی کی خرابیوں کو دور کیا جائے بلکہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایک انتقامی جذبے کے تحت وہ

انہیں دور کرنا چاہئے - اگر واقعی میں وہاں ایسی چیزیں ہوئی ہیں تو ان کو دور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے - اگر وہ نہیں ہوتی ہیں تو اس رپورٹ نے جو سفارشات کی ہیں ان پر انہیں پوری طرح سے عمل کرنا چاہئے -

آج کی اپنی تقریر میں شری پرکاش ویر شاستری نے دو ایک باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا میں جواب دینا چاہتا ہوں - شاید شری پرکاش ویر شاستری پروفیسر حبیب کی ذات سے واقف نہیں ہیں - ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ پروفیسر حبیب اس ملک کے ایک ماہر تعلیم ہیں - وہ اس ملک کے ایک بڑے مورخ ہی نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑے وطن پرست بھی ہیں - ان کے کردار سے ہم سب واقف ہیں اور ان کے عمل کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں - شاید شری شاستری جی کو ہماری سیاست کا وہ زمانہ یاد نہیں جب علی‌گڑھ میں مسلم لیگ اور اس قسم کے دوسرے مناصر کا غلبہ تھا - پروفیسر حبیب وہ تھے جنہوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا - پروفیسر حبیب ان تمام جلسوں کے لئے ذمہ‌دار تھے جن کو علی‌گڑھ میں پنڈت جواہرلال نہرو جیسی عظیم الشان شخصیتوں نے خطاب کیا تھا -

ان کی کتاب کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے - میں سمجھتا ہوں شاید یونیورسٹی کے معاملات کو اور پیچیدہ بنانا چاہتے ہیں - میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری یونیورسٹی کا تعلق ہے - ہمارے تعلیمی مراکز کا تعلق ہے - ہمیں مذاہب سے الگ ہوکر ان کی دیکھ بھال کرنی چاہئے - چونکہ میرے لئے یہ از بھائی ضروری ہے اور اس کو میں نہایت اہم سمجھتا ہوں کہ ہم اس مسئلے کو اس انداز سے دیکھیں کہ اگر ایک یونیورسٹی نے مالی یا تعلیمی معاملوں میں یا داخلوں کے معاملے میں کوئی ناجائز حرکتیں کی ہیں تو یقیناً میرا فرض ہے کہ میں مطالبہ کروں اس ایوان سے - ایجوکیشن منسٹری سے - تمام ذمہ‌دار لوگوں سے - جن پر اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسی باتوں کی تحقیقات ہونی چاہئے -

اس کے لئے کسی مذہب کے یا کسی قوم کے نمایندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے - ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ میں تمام تعلیمی خادمیں سے مطالبہ کروں کہ اگر وہاں اس قسم کی ظلمیاں ہیں تو ان کو دور کیا جائے - جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے یونیورسٹی کے ان لوگوں کو جو اس سے متعلقہ ہیں اسے مان لینا چاہئے اور جو غلطیاں ہیں ان کو

نام سے بدنام کرتے ھیں تو یہ درست نہیں ھے -

جہاں تک دوسری بات کا تعلق ھے جن کا شریمتی رہلو چکرورتی یا ھیم بروا صاحب نے ذکر کیا ھے ان کی تحقیقات ھونی چاھئیے ۔ اگر ستر ھزار یا پچھتر ھزار کسی کے نام سے یہ بک قلم کاٹ دیا گیا ھے تو اس کی تحقیقات ھونی چاھیئے اور آئندہ کے لئے ان کو وارننگ دی جانی چاھیئے -

ایک اور تذکرہ کیا گیا ھے - اس کے بارے میں یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کے ممبروں کو سوچنا چاھیئے کہ جو کہا گیا ھے کہ اے - این - خواجہ کی زمین چاھے کم قیمت پر یا زیادہ قیمت پر خریدی گئی ھے - لیکن جب یہ مسئلہ حل ھو رھا تھا تو ان کا اس کمیٹی میں موجود ھونا ضروری نہیں تھا - اس بارے میں یقیناً آئندہ کے لئے یونیورسٹی کے خادمین کو یونیورسٹی کے معاملات میں دخل رکھنے والے لوگوں کو خیال رکھنا چاھیئے -

یہاں یہ بھی کہا گیا ھے کہ وھاں پر کمیونسٹوں کا اثر ھے - وھاں پر جماعت اسلامی کا اثر ھے - میں ان تمام باتوں میں پڑنا نہیں چاھتا ھوں - میں یونیورسٹی نے ان

[شری ع - م - طارق]

انہوں نے انکی اس کتاب کو دیکھا نہیں ھے - اس کا سیکنڈ ایڈیشن یہ ھے - جہاں تک مجھے یاد ھے پروفیسر حبیب ۱۹۴۷ اور ۱۹۴۸ کے درمیان چین گئے تھے اور انہوں نے وھاں چند لیکچر کئے - اس لحاظ سے بھی ان پر انہوں نے زکھک حملہ کرنے کی کوشش کی ھے کہ انہوں نے ماؤتسے تنگ کا نام کیوں لکھا - اس میں کوئی شک نہیں ھے کہ اس وقت چین اور ھندوستان کے تعلقات اتنے بہتر نہیں ھیں جتنے آج سے قبل تھے - لیکن ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا اور نہ ھی شری پرکاش ویر شاستری کر سکتے ھیں کہ ماؤتسے تنگ کی جہاں تک جد و جہد کا تعلق ھے - جہاں تک ان کی طرف سے کی گئی چین کی رھنمائی کا تعلق ھے یا غیر ملکی طاقت سے چین کو آزادی دلانے کا تعلق ھے انہوں نے ایک شاندار پارٹ ادا کیا ھے - اگر ایک مورخ نے اور ایک ذھین آدمی نے انکا نام لے لیا تو آج وہ کیسے کمیونسٹ ھوگئے - اس زمانے میں جب مسلم لیگ کا دور دورا تھا پروفیسر حبیب کانگرسی تھے اور کانگرسی ھونے کی وجہ سے کئی بار ان پر حملے ھوئے - لیکن آج اسی پروفیسر حبیب کو آپ ایک غلط سیاست کو کامیاب بنانے کے لئے کمیونسٹ کے

ہوں کہ اگر یونیورسٹی میں کچھ ایسی بنیادی باتیں ہیں - کچھ گڑبڑیاں ہیں - اندرونی سازشیں ہیں یا باہر کے لوگ یونیورسٹی کے اندرونی معاملات میں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں وزیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کی طرف خاص توجہ دی جائے -

اس وقت ملک میں ایک خاص قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کا ذہن صاف ہو اور بلا لحاظ مذہب اور ملت کے وہ ملک کی خدمت کر سکیں - میں پرکاش ویر شاستری جی سے درخواست کروں گا کہ ان کو اس رپورٹ سے اطمینان ہو جانا چاہیئے تھا اور اطمینان ہو جانا چاہیئے تھا اس بات سے بھی کہ یونیورسٹی داخلے کے معاملے میں ناجائز حرکتیں نہیں کرتی ہے اور ان کو بہ حیثیت ایک اچھے شہری کے اس کو مان لینا چاہیئے تھا - ساری یونیورسٹی کو - اس کی قربانیوں کو - اس کے ماضی کو - اس کے حال کو - اس کے مستقبل کو تاریک بتانا نہ دانشمندی ہے اور نہ دیانتداری - میں بہ حیثیت ایک مسلمان شری ہروانی کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ علیگڑھ یونیورسٹی میں جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہاں ایسے حضرات تھے جن کے ہاتھ میں وہاں کا نظم و نسق ہے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہنگاموں میں کیا کچھ لوگوں کو یونیورسٹی کی ملازمت سے بے دخل کیا گیا ہے اور یہ کہہ کر کیا گیا ہے کہ وہ کمیونسٹ ہیں - میں اس بات کو بہ حیثیت ایک شہری پسند نہیں کرتا ہوں کہ اس طرح کی وجوہات بیان کر کسی کو بے دخل کیا جائے - ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ملک میں خاص قسم کے جذبات پھیلانے کے لئے درست نہیں ہے - میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز دوست شری انصار ہروانی کی ہمشیرہ کو اس واسطے برخاست کیا گیا ہے کہ وہ کمیونسٹ ہیں لیکن ۱۹۴۷ میں انہیں حضرات نے لکھنؤ کے مسلم کالج سے اس لڑکی کو اس لئے نکال دیا تھا کہ اس کا بھائی کانگرسی ہے - میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں - یہاں پر ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے — کہ کیا اس طرح کی باتیں ملک کے لئے خطرہ پیدا نہیں کرتی ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ آج آپ ع - م - طارق کو اس لئے قتل کریں کہ وہ کانگرسی ہے اور جب آپ اس لحاظ سے قتل نہ کر سکیں تو کہیں کہ وہ کمیونسٹ ہے - میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں کی پوری تحقیق ہونی چاہیئے - ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا

[شری ع - م - طارق]

لوگوں کا غلبہ ہوا جو ہندوستان کی تحریک آزادی سے اتفاق نہیں رکھتے تھے - وہاں آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیئے کہ اس کا قیام کن حالات میں اس ملک میں ہوا اور اس کو بنانے کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا - اس کے باوجود بھی اس یونیورسٹی نے ملک کی - نیشنلزم کی اور ملک کی جد و جہد کی جو خدمت کی ہے - اس کو ایک نہیں لاکھوں پرکاش ویر شاستری بھی اس ملک کی تاریخ سے ہٹا نہیں سکتے ہیں -

میں بلراج مدھوک صاحب کی بھی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ جب محمد غوری یا محمد قاسم کا قصہ آتا ہے تو ہمارے جذبات ابھر جاتے ہیں - میں ان باتوں میں یقین نہیں رکھتا ہوں - ان کو سوچنا چاہیئے کہ آج جب آپ تاج محل کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مغل پیریڈ کی یہ یادگار ہے - جب آپ اورنگ زیب کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مسلمان بادشاہ تھا، لیکن جب آپ انگریز کا ذکر کرتے ہیں - اس کے ظلم اور ستم کی بات کرتے ہیں تو آپ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ عیسائی راج تھا - آپ اسے برٹش گورنمنٹ کہتے ہیں - اس کے لئے نہ مسلمان ذمہ دار ہیں اور نہ ہی ہندو ذمہ دار ہیں بلکہ یہ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے اور اس سازش کے لئے انگریز ذمہ دار ہے - جب آپ تاج محل کی بات کہیں تو اسے مغل پیریڈ کی یادگار کہیں - جب اورنگ زیب کی بات ہو تو اسے اسلام کا نمائندہ کہیں اور جب انگریز کا نام آئے تو آپ میں یہ جرات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ اس ملک میں دو سو سال تک عیسائیوں کی حکومت رہی - ان چیزوں کو جب آپ خود اس رنگ میں پیش کریں اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں اس بات کو ڈالیں تو اس کا اثر ان پر برا ہی پڑ سکتا ہے - ان سے آگے چل کر آپ کسی چیز کی توقع کر سکتے ہیں -

بہر حال ان چیزوں کا علیگڑھ یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا - میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت ان واقعات کے بارے میں اور ان سفارشات کے بارے میں کچھ قدم اٹھائے - میں ہروانی صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ یونیورسٹی کو ان باتوں کو ماننا چاہیئے -

میں یونیورسٹی کے خادمین سے ایک چھوٹی سی اور درخواست کرنا چاہتا ہوں - ان کو بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیئے - پچھلی دفعہ ایگزیکٹو کا جب ایلکشن ہوا تھا اس وقت اس میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں - میں درخواست کرونگا کہ آئندہ کے لئے ایسی غلط فہمیوں کا موقعہ نہ دیا جائے اور وسعت قلبی کا ثبوت دیں -]

Shri D. A. Katti (Chikodi): Mr. Chairman, I will restrict my speech to one recommendation that has been made by this Enquiry Committee and I will not take much of the time of the House. The Committee recommends that the post of Pro-Chancellor should be abolished and it gives big reasons for the abolition of the post. I would like to read the relevant portion of the report.

On page 120 under the heading 'unified Control' they say:

> "We are of opinion that in a university, specially of a unitary and residential type, administrative and academic control should be centralised in the office and person of the Vice-Chancellor,..."

that is, the Committee is insisting upon unified control. But further they say:

> "But when a university has a wholetime paid Vice-Chancellor, we see no justification for creating yet another post of Pro-Vice-Chancellor of almost equal rank which may lead to friction and to the formation of divided loyalties...."

These are the reasons given for the abolition of the post of the Pro-Vice-Chancellor. But, according to me, the reasons given by the Committee do not appear to be sound. As regards the first ground, the Committee says that there should be unified control and for that purpose the post of the Pro-Vice-Chancellor should be abolished. But in the course of the enquiry the Committee came to know that the Vice-Chancellor of the Aligarh Muslim University has made use of his emergency powers in sheer disregard of the Academic Council, the Executive Council and the Finance Committee. This has been referred to by many of my hon. friends here. Therefore I had expected the Committee to recommend the curtailment of or judicious control over the exercise of the powers of the Vice-Chancellor. But instead of doing that, the Committee wants the whole control to be centralised in a single hand, that is, of the Vice-Chancellor. I do not think this is any sound ground. Also, it is not desirable.

As regards the second point, the Committee entertains a fear that there is the possibility of some sort of friction or conflict between the Pro-Vice-Chancellor and the Vice-Chancellor. I do not agree with this also, because I may say, for example, there is a man who has got a wife and there is a conflict between the husband and the wife. The husband may at the most divorce his wife and marry some other woman. That does not mean that because there is conflict between the husband and the wife, they should not marry at all. Nobody will agree with this. There is not at all a question of a conflict for the simple reason that the Pro-Vice-Chancellor's appointment is made by the Executive Committee. The Pro-Vice-Chancellor is selected by the Vice-Chancellor. So, he can very well choose such a person in whom he can repose his confidence and who can extend his co-operation. For that reason also there is no fear of any conflict between the Pro-Vice-Chancellor and the Vice-Chancellor.

Secondly, the statute provides that the Pro-Vice-Chancellor shall perform such duties which are assigned to him by the Vice-Chancellor. This reduces all area of any conflict between the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor. There may be some difference of opinion. Such difference of opinion should be there. It will be there. For example, there are the Deans, the Pros and the Heads of Departments. It is not necessary that they all should be unanimous on certain issues. There is bound to be some difference of opinion and that difference is certainly a healthy thing for the functioning of democracy.

14.45 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

That is rather essential. That is why I do not think that because there is the possibility of some conflict between the Pro-Vice-Chancellor and the Vice-Chancellor the Pro-Vice-Chancellor's post should be abolished sounds so logical.

This post exists in the Banaras Hindu University. This post exists in many other universities in foreign

[Shri D. A. Kutti]

countries, for example, in the universities in the UK and the USA. Therefore when this post of Pro-Vice-Chancellor can continue in the Banaras Hindu University, why insist upon the abolition of this post in the Aligarh Muslim University? I do not understand that. Why do away with it at all? Moreover, this post of Pro-Vice-Chancellor has been there since the inception of this University. It has stood the test of time. There was no such conflict between the Pro-Vice-Chancellor and the Vice-Chancellor at any time before. Now it must have occurred on account of some political acticity or communalism in the University. But that does not mean that we should do away with the post of Pro-Vice-Chancellor.

This Comittee had referred this matter to Dr. C. D. Deshmukh and this is what he said:

> "Dr. Deshmukh, however, went on to state that though he favoured the abolition of the post of Pro-Vice-Chancellor, he was of opinion that a Vice-Chancellor did need the help of a senior and experienced officer to relieve him of day to day routine administration, so as to devote part of his time to larger matters of policy and for participation in conferences arranged by the University Grants Commission, the Central Ministry of Education and other agencies of an academic and cultural type."

This need has been expressed by Mr. Deshmukh and this need cannot be satisfied by the appointment of a Rector. The Rector is merely a glorified clerk. At the most he is a Secretary. He cannot attend the meetings. He cannot express his views unless he is asked to do so by the Vice-Chancellor. He cannot do the duties of a Pro-Vice-Chancellor. The nature of both the Universities at Aligarh and Banaras is such that very often the Vice-Chancellors go out of headquarters. In the absence of the Vice-Chancellor somebody competent enough must be there to perform the duties of the Vice-Chancellor. These duties cannot be performed by the Rector.

The Committee recommends for him a salary of Rs. 1,500. What for? For routine administration? The University can delegate the powers to the Deans and to the Heads of Departments. These things can very well be done by those people. You may not have a Rector at all. Therefore to abolish the post of Pro-Vice-Chancellor does not seem to be desirable and this particular recommendation should not be implemented.

I have heard most of the hon. Members and have sensed a sort of communal angle in some of the speeches. Now the need for national integration is badly felt, particularly at this time. This need was not felt so badly at any time in the past. When we are thinking of national integration, we should not allow such tendencies to grow. Therefore I am of the opinion that the Aligarh Muslim University at Aligarh and the Banaras Hindu University at Banaras should be done away with. They should be scrapped. Then only there will be some healthy growth. Why should we have a Muslim University and a Hindu University? They do not impart any culture. Both the universities teach arts and sciences. Why should they be named as Muslim University and Hindu University? Times have changed. Therefore I think it would be desirable to do away with these names and have some other names under which to run these universities.

With these words I conclude my speech.

Mr. Speaker: How long does the hon. Minister propose to take?

Dr. K. L. Shrimali: About forty to forty-five minutes.

Mr. Speaker: And then there is a right of reply, I think.

Some Hon. Members: Yes.

Mr. Speaker: Then I think there is no chance for any others. The hon. Minister.

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): Mr. Speaker, Sir, in Vigyan Bhavan we are having a conference at this time, a conference of all the Chief Ministers, which has been called by our Prime Minister to discuss the problems of national integration. It is, therefore, of the greatest importance that when we are discussing this question we should remember the background of our country, the present situtation under which this question is being thought about. It is of the greatest importance at the present juncture of our history that we stand united as a nation, by showing a spirit of tolerance, understanding and appreciation of each other's religion and culture.

I am making these preliminary remarks because from some of the statements which were made by hon. Members one got an impression that they were not making these statements from the broader national point of view but from a narrow communal angle.

Before I answer some of the points that have been raised during the course of the debate, I should like to dispose of one recommendation which this Committee had made to the Government. On page 140 of its report the Committee says:

> "We were gravely perturbed by statements made before us by highly esteemed Muslim witnesses, about whose active support to the cause of India's freedom struggle and the preservation of its unity there cannot be the slightest doubt, that their community was being discriminated against in the matter of higher education, in various regional universities. Although these witnesses were not able to cite specific instances of such discrimination they appeared to be really exercised over the situation and in our opinion it would be desirable on the part of Government or any other competent body to investigate the matter fully with a view to finding out the facts."

Shri Khushwaqt Rai (Kheri): These are the people who have spoken.

Dr. K. L. Shrimali: "Such vague fears and generalisations are bound to prove harmful for the growth of a healthy national life and the facts must be established so that appropriate action could be taken, if necessary, or their fears and misgivings set at rest".

In order to set their fears and misgivings at rest, the Government have made a full enquiry into this matter, and we have now got figures from almost all the universities in India, scientific and technological institutions, which establish beyond doubt that there is absolutely no discrimination as far as admission of Muslim students in any of the universities is concerned. And if any of the hon. Members have any specific instances before them—I wish they could have quoted them before the Committee also—the Government of India would stop paying any grants to them.

Under the leadership of our great Prime Minister fortunately we have developed a sound secular democratic set-up in this country. And I am proud to say that as far as higher education in this country is concerned, there is absolutely no reason to doubt that any kind of discrimination is being made against the minority community.

I would not like to inflict the figures on this House, but we have now sufficient evidence to show that students are being admitted, as far as Hindus

[Shri D. A. Kutti]

and Muslims are concerned, absolutely on the basis of merit.

I would also like to draw the attention of the House here to a comparative study of the grants paid to the Central Universities by the Central Government and the University Grants Commission from 1947-48 to 1960-61. It will be observed that in the case of the Aligarh Muslim University the grant of Rs. 5·61 lakhs made in 1947-48 has risen to Rs. 57·93 lakhs in 1960-61. The grant in the case of the Banaras Hindu University has risen from Rs. 10·94 lakhs in 1947-48 to Rs. 92·83 lakhs in 1960-61 I am giving this comparative statement since these questions of the Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University were raised. It would be found that the increase in the case of the Aligarh University has been 11½ times compared to an increase of 8½ times in the case of the Banaras University. So, if there has been any discrimination, it has been discrimination, in favour of the Aligarh University. But I am proud of this fact. I would like hon. Members to remember that the Government have strong faith in a secular democracy. I would like hon. Members to quote one example of a similar nature where a university managed by a minority community has been treated so liberally as the Aligarh University has been treated as far as the Government of India grants are concerned.

Allegations were made at the time the Muslim Convention was held; allegations were also made before this Committee, and I am sorry to find that the Committee has recorded that these statements were made by people who had taken a very important part in the national struggle. I do hope that these Members would make a thorough and proper enquiry into this matter and disillusion their minds about the misgivings which they have on this question. And I state here on the floor of this House that if they can bring before me one single instance where discrimination is made against Muslim, the Government would stop all grants to that institution, as far as the Government of India are concerned. I can say this also on behalf of the State Governments that no grant will be made to any institution which makes discrimination against Muslims.

Shri Balraj Madhok: If there is discrimination against Hindus would my hon. friend do the same thing? There is discrimination against Hindus in the Aligarh University.

Dr. K. L. Shrimali: I think I need not answer the hon. Member.

Shri Vasudevan Nair (Thiruvella): There is repeated allegation that there is discrimination against non-Muslim students in the Aligarh University. It was refuted by some hon. Members. We would like to know what the position is.

Dr. K. L. Shrimali: I am coming to that. Well, Sir, as far as the Aligarh University is concerned, it has a history. It is our desire that we should forget all that happened in the past in the Aligarh University before independence. We should now look towards the future. We should try to make it a strong national institution which may become a centre of learning of Islamic studies and culture, the greatest centre in the whole of Asia, and, I would like to say, in the world. I would like people to come over from all over the world to this University so that they may understand that here in this country, people of minority communities are allowed to study, to carry on their studies in an atmosphere of perfect freedom.

15 hrs.

The question of admission has agitated the minds of people. The report has gone into full details and I am in general agreement with the statements which the report has made

in this connection. It is quite obvious that there should be a larger number of Muslim students in the Aligarh University. It is also obvious that some preference should be given to Muslim students who have been old boys of that University. I am also glad to say that under the able Vice-Chancellorship of Dr. Zakir Hussain, one of our noblest and ablest Muslims, who played a very important role in the struggle of National Independence, the University has been attempting to change its character. It is becoming gradually a truly national institution.

I think I ought to explain about my conduct also. It was questioned as to why I did not appoint a Visitor's committee. It was said, that in the case of the Banaras University we appointed a Visitor's committee, why did we allow the Aligarh University to appoint its own committees? I would like to give the whole background to hon. Members. Three years back, I called the Vice-Chancellor and told him that the House must be set in order. I called him once, twice, thrice. I also spoke to the Pro-Vice-Chancellor. The Ministry also sent several communications. This has been happening for the last 10 years. Unfortunately, the Vice-Chancellor did not pay sufficient heed to our requests. As the Committee has rightly pointed out, there was complete apathy with regard to the utilisation of public funds. Complaints were made by the Comptroller and Auditor General year after year No attempt was made by the University to remove these objections or clear up those objections. That, I thought, was a very serious state of affairs. I requested the Vice-Chancellor several times to look into the matters; but no attention was paid to it. Therefore, I had no other alternative but to make an enquiry into the affairs of the University and the report has now vindicated our stand. I think the enquiry was fully justified. It has done a lot of good to the University. Just at the time when I was appointing the Visitor's committee, I was going to send the proposal to the Visitor, the Vice-Chancellor knew that we were going to take this action. He and some members of the Executive council came to meet me in deputation. They requested that the committee might be appointed by the University. It may be an error of judgment; but in the best interests of the university, I agreed to the request. They advanced the argument that if the Visitor's appointed a Committee, there would be an impression in the outside world that the affairs of the University were in a very serious state. I did not want to do any harm to the University. Therefore, when this deputation came, I accepted the request of the Vice-Chancellor and allowed the university authorities to appoint their own committee.

Shrimati Renu Chakravartty: The hon. Minister said all this last time. He is repeating exactly the same things.

Mr. Speaker: There are now other hon. Members who are new.

Dr. K. L. Shrimali: I have to explain that.

Then, Shri Prakash Vir Shastri asked for a Half-an-hour discussion in this House,. As you are aware, I was most reluctant and I begged of you not to allow this discussion since the University had already appointed a Committee. But, I had to carry out your orders and the discussion was held. Unfortunately, during the course of the discussion, a great deal of heat was aroused. Shri Prakash Vir Shastri made allegations with regard to Mr. Khwaja's land, Mr. Saiyadan's house and various other allegations which have not be substantiated. I think it was a great mistake on the part of Prakash Vir Shastri. Another Member Shri Vajpayee made such wild allegations. Shri Vajpayee is not here. But during the course of his speech, he said that the University had ordered for some machinery worth several lakhs

[Dr. K. L. Shrimali]

and all that machinery was sent to Pakistan. Without any basis, any foundation, that an hon. Member of the House should make such a wild allegation is a serious reflection on our duties and responsibilities. What a great harm, Shri Vajpayee did to the University—all the newspapers flashed this news.

Shrimati Renu Chakravartty: He was challenged. He said, on my own authority I say, I have got very good information.

Dr. K. L. Shrimali: That allegation was made. When the Enquiry committee requested him to give evidence, I am told that he never appeared before the Enquiry Committee. This is the type of responsibility which the hon. Member had towards the public.

Unfortunately, then again, some controversy started. The Vice-Chancellor made statements. In my opinion, it was wrong on the part of the Vice-Chancellor to make the statements since the committee was appointed to look into all these matters. The Committee rightly took strong objection to the Vice-Chancellor's statements. They rightly felt there was need to have the committee. There was a suggestion that we should add some more Members. I was reluctant, I must say honestly, because we had appointed a high-power committee of people who were not connected with any community. There was Shri G. C. Chatterji, one of our eminent educationists; there was Shri A. R. Wadia of the Tatas Institute, Shri K. S. Malhotra, one of our officers who has been a great financier serving in the Punjab. These three people were selected carefully. They did not belong in any way to the two communities, Hindus or Muslims. There was a great deal of pressure....

Pandit K. C. Sharma: (Hapur): Why did you forget a High Court Judge?

Dr. K. L. Shrimali: The High Court Judge came later. We had to add two more members: Shri P. N. Sapru and Shri M. A. Shahmiri. I am grateful to these two members and also the other three members. They have done a very fine work. It was a very difficult task which they had to perform, a very unpleasant task. They have done an admirable job. They have tried to place the facts in the proper perspective. I would be failing in my duty if I did not express my gratitude to all these Members who had to pass through various difficult stages. In the first place, there was some difficulty with the Vice-Chancellor and they felt that there was not that co-operation which they should have had and therefore they resigned. Then, the new Members were added. It was a rather very awkward situation. The Committee was appointed. Later on, new members were added. The whole Committee worked as a team and they have done an admirable job. I think it is my duty to express my gratitude to this Committee. I wish that having appointed this high-powered committee, the university had said 'It is our committee, we accept all its recommendations.'. I am sorry this has not been done. I wish the university had exercised greater responsibility in this matter. This was their committee. It was appointed by them. It is true that names were suggested by me, but the members of the committee were men of the highest ability, character and integrity, interested in the real welfare of the university. The university should have said 'We are grateful to the committee, and we accept all the recommendations'.

Shri Hem Barua: The committee was appointed by the executive council.

Dr. K. L. Shrimali: Unfortunately, this was not done. Now, Government have to consider what action to take in this matter, and Government will take action which is in the best interests of the university.

Then, Shri Prakash Vir Shastri, during the course of the discussion, raised a question with regard to persecution of some witnesses who had appeared before the committee. He also said that he was going to hand over some letters to me, and if he has any documents or any letters, I am going to look into the matter. It is true that when this question was raised in this House, I had said that the Vice-Chancellor had a right to sit on this committee.

According to Statute 3(1), the Vice-Chancellor can be present and address, all the meetings of the committee, that is, a committee appointed by the university. Therefore, he exercised his right. If the Visitor had appointed the committee, it would not have made any substantial difference, because under section 13(2)(a) of the Aligarh Muslim University Act, the Vice-Chancellor is entitled under statute 3(1) to be present and to address the meetings of the committee. So, in either case, that would not have made any difference, because either the Vice-Chancellor or his representative should have been present, if the committee had been appointed by the Visitor.

I had said in this House that since there were allegations against the Vice-Chancellor himself, he would have discretion not to sit on this committee, and I still maintain that it would have been in the interests of the university, if the Vice-Chancellor had not sat on this committee. It would have been much better if he had sent somebody else as his representative. It is a well-established convention. For instance, if there are allegations against me, obviously, I cannot expect my subordinates to come and give evidence before a committee on which I am sitting.

However, as far as I can see, the committee had done an admirable job, and in spite of the handicaps which they have had to face, they have made a very thorough enquiry into all the allegations that have been made.

I could not order the Vice-Chancellor, because the Act was there, and he was acting according to the provisions of the Act, and he had a right to sit on it, and he sat on it. As I have said, even if the Visitor's committee had been appointed, it would not have made any difference.

I had also said probably in this House that for all practical purposes, Government would treat this as the Visitor's Committee, and we are going to treat this as the Visitor's Committee, as far as the implementation of the report is concerned. But I would not have prevented the Vice-Chancellor from attending any of the sittings of the committee. He did attend all the meetings, or practically all, when the evidence was being taken, and when discussions were taking place; he kept out only during the last stage when the committee started deliberations and writing of the report. In my opinion, he would have served the interests of the university best, if he had kept out of this discussion and sent somebody else as his representative. Anyway, I do not think we can go into that matter again at this stage.

Shri Hem Barua: The hon. Minister had given this advice in the last speech also.

Dr. K. L. Shrimali: I think I had said this last time; this was a broad hint which he should have accepted. If Shri Prakash Vir Shastri has any instance where there has been persecution of a witness, I think it is the duty of Government to protect such witnesses. I am going to look into this matter, if he produces any evidence to show that there has been persecution of witnesses. Of course, if he says something on the floor of the House, it is not possible for me either to agree with him or to reject it; but if he has any specific instance, and if he gives it to me, I am going to look into that matter.

Several hon. Members made reference to the presence of communists

[Dr. K. L. Shrimali]

and communalists, in this 'varsity. Shri Prakash Vir Shastri brought in a new category namely the communalist-communists in the Aligarh Muslim University. As far as Government's attitude in this matter is concerned, Government has always believed in the academic freedom of the universities. In fact, the very fact that we have created the University Grants Commission shows that Government are anxious to keep politics out of the universities. There must be full academic freedom in the universities. But I must also say with all the emphasis at my command, that Government also expects cent per cent. loyalty from people to their Constitution and to their State; there can be no compromise as far as this matter is concerned.

Somebody here on the floor of the House said that recently a professor who is a member of Jamiet-e-Islami has been appointed as a member of the university. We know something about this organisation. It is preaching a dangerous ideology in this country. They want to set up again a theocratic State in this country. And we know that in the Aligarh University, at present, there are various kinds of forces that are working. I am not going into what their personal views are and what their politics are. But I wish to make one thing very clear, namely that Government will not tolerate, and will not make any compromise as far as this basic issue is concerned. It expects cent per cent loyalty to the Constitution and to the State from all its citizens. If there is anybody who in any way makes an attempt to do anything which undermines the loyalty, Government will take firm action in this matter, academic freedom or no academic freedom. I wish to make this very clear in this House. A university should certainly have freedom in order that it might be pursuing the truth, and in order that the students and scholars might seek knowledge, but freedom is not given to destroy freedom itself. We know by experience that in several countries people have misused freedom to destroy freedom, and we are aware of that great danger which exists in this country, and Government will do everything that is possible to counteract that danger. So, I wish to make that very clear. Whether they are communists or communalists or communalist-communists, whatever creed they belong to, I wish to make this very clear; let it be Aligarh Muslim University or Banaras Hindu University or whatever other university it may be; let them be clear about this matter. There will be no compromise on this issue.

Then, some Members suggested that Government should do away with the terms 'Hindu' and 'Muslim' in the names of the universities. I appreciate the sentiment which they have expressed. And if this House can come to an agreement on this issue, I am prepared to accept the suggestion. But let us do it with good-will. Let us not create any bitterness on this issue. These universities have a certain tradition and a certain past history. If all the Members of the House can come to an unanimous agreement in this House, it will set a great example before other people. We all believe in national integration. Let that be the beginning for national integration in this country. I am prepared to accept this proposal provided there is complete unanimity on this issue. I do not want that any passions should be roused in this matter.

Shri Rajendra Singh (Chapra): Will the hon. Minister create an opportunity so that the House can come to that conclusion?

Dr. K. L. Shrimali: Certainly there will be opportunities. Lastly, I should like to say that this report which has been submitted by this very able and high-powered committee is not very complimentary to the university administration. I must make

this very clear. There are serious charges of maladministration, inefficiency, misuse of public funds etc. in this report. And Government cannot remain completely apathetic towards these matters. Government have a certain duty towards the public. Universities have a duty towards society. I think the Aligrah University should seriously consider these matters and should set their house in order as quickly as possible, if they wish to retain their freedom in the University. I am saying this not only to the Aligarh University but in respect of all Universities which receive Government grants.

I would request the House to forget the past. The post has gone. Unfortunately, the Aligrah University had a past not very glorious before independence. It has passed through the birth pangs of building up new traditions and at this stage, it would need all the care, tenderness and sympathy of all sections of the House.

There are difficulties. In the Aligrah University, at present there are various forces which are working, fighting against each other and trying to run down each other. Many of these things have come out from the Aligrah University itself.

An Hon. Member: What are those forces?

Dr. K. L. Shrimali: By this time, the House should be aware of those things. So many views have been expressed that it is not necessary for me to mention them. Let there be only one ideal as far as the University is concerned, namely, service to the nation and loyalty to the State. That should be the ideal for all Universities, whatever forces may be working there. Therefore, I would appeal to the House and also the University to look towards the future.

This is a great national institution. It has been set up to serve a very important purpose in our national life. We have in this country diversity of cultures, different religious and different languages. Government have given very liberal grants to this University so that it might become a centre of learning, culture and Islamic studies. Government would like to do everything to develop this institution. Let the Muslim community realise their responsibility in these matters. Let not these matters be treated lightly.

Shri A. M. Tariq: Why does he say Muslim community? It is the Indian community.

Dr. K. L. Shrimali: I do not have ing to the Muslim community because they have a certain responsibility as far as this University is concerned. Let them give serious consideration to this whole Report before they reject its rcommendations. It deserves very serious consideration. But I am afraid the matter has been treated lightly. This was a high-power Committee. I had assured the House that it was almost a Visitor's Committee and that Government would treat it as a Visitor's Committee. After that assurance, they should have acted with a greater sense of responsibility. I am afraid that has not been done. That has been the feeling of Members from practically all sections of this House.

I would appeal to the Muslim University to review the whole position again. Government, of course, will do their duty as best as they can.

Shri Khushwaqt Rai: In the beginning the hon. Minister referred to same remarks on page 140. Is he in a position to disclose the names of those reliable witnesses?

Dr. K. L. Shrimali: I do not have the list of witnessess. The Aligrah University conducted this inquiry. But I am told that very prominent

[Dr. K. L. Shrimali]

people have said that there is discrimination. I am very glad to say that there is absolutely no discrimination in any University at present. I have collected the information and I am prepared to place it on the Table of the House if necessary. There are Muslim students studying in most of the Universities, scientific and technological institutions. There is absolutely no discrimination. Therefore, I would like to disabuse the minds of those Members who think like that. They need not have those misgivings and fears about this matter. Under the leadership of our great Prime Minister, we have developed very sound traditions in this country and I am very proud that we have this University to which every possible assistance is being given to develop. All our Universities today are free from any tinge of communalism.

Shri Hem Barua: According to the provisions of the University Act, when a Committee is appointed by the Executive Council, the Vice-Chancellor automatically becomes an ex-officio member of that Committee, but when a committee is appointed by the Visitor, he does not become an ex-officio member of that Committee. He can only address it. That is the difference.

Mr. Speaker: Therefore?

Shri Hem Barua: He was basing his argument on this and saying that there was no difference.

Dr. K. L. Shrimali: As far as I have been able to understand—I do not have the Act here—the University would have been entitled to appoint a representative. This note is from the University itself. It says that the University would have been entitled to appoint a representative who would have had the right to be present and be heard by the Inquiry Committee under section 13( )(a) of the Aligarh Muslim University Act. As the Committee was appointed by the University authorities, the Vice-Chancellor was entitled under Statute 3(1) to be present and address the meetings of the Committee. So the provisions are clear.

Shri Hem Barua: He does not become a member.

Dr. K. L. Shrimali: It would not have made any difference.

Shri Hem Barua: He is not a member of the Committee. My point is this: when a Committee is appointed by the Executive Council, he automatically becomes an ex-officio member thereof under the provisions of the Act.

Dr. K. L. Shrimali: He need not have gone there. It was quite unnecessary for the Vice-Chancellor to be present. He could have sent one of his representatives, if it was necessary. I wish the Vice-Chancellor had exercised his discrition not to sit in the Committee. It would have helped the University considerably and people would not have all these doubts which they have in their minds; it would have strengthened the position of the University.

I think the House should not go into this matter again. Let us forget the past. Let us think of the future of the University and built it up.

I do not accept the amendment that has been moved by Shri Bal Raj Madhok. I request him to withdraw it.

Shri Jamal Khwaja: I want to ask a question.

Mr. Speaker: I am not going to allow any further question; we are encroaching on the time of the other business.

Shri Rajendra Singh: May I ask a question?

Mr. Speaker: No. Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं इन सारी चर्चाओं को सुनने के बाद फिर अपने उन शब्दों को बलवती भाषा में और संतुलित शब्दों में दुहराना चाहता हूं कि इन चर्चाओं के पश्चात् मेरा यह निर्णय और भी पुष्ट हो गया है कि इस विश्वविद्यालय की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति जी की ओर से जांच कमेटी अवश्य बिठायी जाये और तब विश्वविद्यालय की सही स्थिति का पता लगाया जाये ।

कुछ सदस्यों ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा की कि वाइस चांसलर गवाही के समय उपस्थित थे लेकिन जिस समय निर्णय लिये गये थे उस समय वाइस चांसलर उपस्थित नहीं थे । यह कितनी हास्यास्पद सी बात है । उन गवाहियों के आधार पर ही तो कमेटी को निर्णय लेना था । गवाहियों से अतिरिक्त आधार पर तो कमेटी निर्णय नहीं ले सकती थी । जब उन सारी बातों के समय वाइस चांसलर उपस्थित थे तो निर्णय के समय पीछे हट भी गये तो कमेटी किसी और आधार पर कैसे निर्णय ले सकती थी ।

दूसरी तो सब से बड़ी बात मैंने कही और मैं चाहता था कि शिक्षा मंत्री जी शायद अपने वक्तव्य में उसका स्पष्टीकरण करेंगे, वह यह थी कि जब आपने इस हाउस में और राज्यसभा में ये शब्द कहे कि यह चार आदमियों की जो कमेटी एप्वाइंट हुई थी यह विजिटर कमेटी के समान थी, तो मैं जानना चाहता था और उनकी ओर से यह उत्तर भी आना चाहिए था कि फिर क्या कारण था कि उस कमेटी में दो और व्यक्तियों की वृद्धि रहस्यमय ढंग से क्यों की गयी ? किस प्रकार का रोल उन दो व्यक्तियों का रहा वह तो रिपोर्ट को देखने से ही पता चल सकता है, मुझे उसे अपने शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं ।

एक साहब ने कहा कि जितने भी आरोप लगाये गये थे वे सारे के सारे निराधार साबित हुए । कमेटी स्वयं अपनी रिपोर्ट में कहती है कि बहुत बातों के लिए जो सामग्री कमेटी प्राप्त करना चाहती थी वह नहीं दी गयी । एडमिशन के सम्बन्ध में रिकार्ड नहीं दिये गये, एग्जामिनेशन्स के सम्बन्ध में रिकार्ड नहीं दिये गये । मैडीकल कालिज के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि उसमें १,२६,४७५ रुपये की रकम की बात थी, उसके रिकार्ड पेश नहीं किये गये ।

डा० का०ला० श्रीमाली : रिकार्ड हैं ही नहीं तो कहां से देंगे ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि जब रिकार्ड है ही नहीं तो वह कहां से लायें । कमेटी ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के रिकार्ड रूम में सन् १८७७ और १८७८ तक के रिकार्ड तो मौजूद हैं पर ये रिकार्ड वहां नहीं हैं। इसका सीधा सादा मतलब क्या है यह मैं स्पष्ट भाषा में पूछना चाहता हूं । यह कहना सही नहीं है कि इसमें पैसे की कोई बात नहीं थी । विश्वविद्यालय का ७८ हजार रुपया बट्टे खाते डाल दिया जाता है वह व्यक्ति हिन्दुस्तान में कानपुर में बैठ कर पेंशन ले रहा है, और लिख दिया जाता है कि वह पाकिस्तान चला गया ।

जांच समिति ने लिखा है कि उसकी नियुक्ति से पूर्व १३ लाख रुपये के सम्बन्ध में पता नहीं था । और इसी कारण यह रिपोर्ट पूर्ण नहीं है कि उसको सारी सामग्री नहीं दी गयी ।

मैं फिर अपने वक्तव्य को संक्षिप्त सी भाषा में दुहराता हूं कि जहां तक उन चार व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिनको समिति में नियुक्त किया गया था उनकी नीयत पर किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको पूरी सामग्री न मिलने के कारण वह सचाई से निर्णय कैसे ले सकते थे ।

एक दो बात और कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं जहां तक इस बात का सम्बन्ध है बहुत से महानुभावों ने

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मेरी बात को प्रभावहीन करने के लिए कहा कि इस विश्वविद्यालय ने खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे व्यक्ति पैदा किये। मैं ने तो विश्वविद्यालय के सन् १९४७ के पहले के किसी एक शब्द को छुआ तक नहीं। अब अगर मैं यह कहता कि इस विश्वविद्यालय ने शेख अब्दुल्ला और लियाकत अली पैदा किये तो अलबत्ता उसके जवाब में आप यह कह सकते थे। जब सन् १९४७ के पहले कि किसी रिकार्ड को छुआ तक नहीं गया तब उन बातों की दुहाई देने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन जहां तक विश्वविद्यालय की पुरानी स्थिति का सम्बन्ध है मैं ने कहा कि डा० जाकिर हुसैन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि इस विश्वविद्यालय की स्थिति को सम्हालने का प्रयास किया, इसको राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहा और इसमें मिली जुली संस्कृति का विकास करना चाहा लेकिन उसके पश्चात् विश्वविद्यालय का स्वरूप बिगड़ गया। आक्षेप तो मेरा वहां पर है। चर्चा में एक साहब खड़े हुए लेकिन बजाय इसके कि वह मेरे ठोस आक्षेपों का जवाब देते, पानी पी पी कर गालियां ही देते रहे। बजाय इसके कि वह कोई तथ्य पेश करते और मैं उसका जवाब देता वह मुझे कोसते ही रहे। उन्होंने यह कहा कि मैं ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री को एक पत्र लिखा था लेकिन शास्त्री जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऐसे महत्वहीन पत्रों का जवाब देना अपने समय की बरबादी समझता हूं। पत्र अगर जवाब देने लायक होता तो मैं उसका जवाब देता। आपसे यह पूछा गया था कि प्रेस के पीछे जितनी जमीन है और जिसको कि तीन रुपये गज के हिसाब से लिया गया है उसी जमीन से लगती जमीन ३५ नये पैसे, १७ नये पैसे और ५ नये पैसे गज बिक रही है। वह एग्रीकल्चरल लैंड है और इससे ज्यादा उसकी कीमत क्या होगी। विश्वविद्यालय में लगने वाला पैसा राष्ट्र के गाढ़े पसीने की कमाई है और एक एक कौड़ी को हमें सावधानी से खर्च करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र सिंह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने ख्वाजा साहब के पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझे एक पत्र लिखा लेकिन मैं ने उस पत्र को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि उसका उत्तर दिया जाय। मैं किसी को इतना आवश्यक नहीं समझता कि उसका पत्र चाहे वह महत्वपूर्ण न भी हो तो भी उसका उत्तर दिया ही जाये। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है और इसका उत्तर आप मुझ से नहीं पूछ सकते। मैं चाहता हूं कि अभी तक उस भूल को नहीं सुधारा गया है तो अब इस भूल को सुधारा जाय क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापिस आ जाय तो उसको भूला नहीं समझा जाता है। जांच समितियों को आवश्यक सामग्रियां नहीं मिल सकीं और इन ही कारणों से वह पूरी अपनी सम्मति नहीं दे सकीं।

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप से यह अर्ज करना है कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जब यहां पर यह अभियोग लगाये थे और उन अभियोगों को साबित करने के लिए श्री जमाल ख्वाजा ने उनको चिट्ठी लिखी और उसकी जानकारी मुझ को भी है और मैं ने भी उनसे विनय की थी कि वे ख्वाजा साहब को उनकी चिट्ठी का जवाब भेज दें। अब शास्त्री जी यह कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब का पत्र इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उसका उनको जवाब दिया जाता तो क्या शास्त्री जी ही अकेले यहां पर बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ? यहां पर सारे माननीय सदस्य महत्वपूर्ण हैं और उनमें हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप को मालूम होना चाहिए कि मैं ने व्यक्ति को महत्वपूर्ण होने न होने को नहीं कहा बल्कि मैं ने तो कहा था कि मैं ने उनके द्वारा लिखे हुए उस पत्र को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि उसका मैं जवाब देता।

Shri Jamal Khwaja: The hon. Member said in Hindi:

"पानी पी पी कर मैं ने उन को गालियां दीं।" I think it is unparliamentary to say that I had abused him "पानी पी पी कर गालियां दीं"। I think that the hon. Member sould withdraw these words. I spoke and referred to him with the grestest respect, and used parliamentary language. It is wrong to say "पानी पी पी कर मैं ने उन को गालियां दीं"। This is undignified, and he must be asked to withdraw these words.

श्री अ० मु० तारिक : मैं इस बात का गवाह हूं कि गाली तो उन्होंने दी लेकिन पानी पी कर नहीं दी।

میں اس بات کا گواہ ہوں کہ گالی دو انہوں نے دی لیکن پانی پی کر نہیں دی۔

Mr. Speaker: I am really surprised that with respect to the Aligarh University there must be so much quarrel inside the House. All that I can say is that after having heard both sides—to a large extent I was present here—I feel that these are matters where the hon. Minister must himself have brought the report for discussion before the House because there is so much of contention, and not left it to an individual non-official Member to bring it up. Is he not interested in it? After all that he has said, it is clear that he must have taken the initiative himself. I would urge upon all hon. Ministers to decide which matters they must bring up. If perchance an hon. Member did not bring it up here, should if go unnoticed?

I am surprised at this. Thais is very important matter. While Shri Prakash Vir Shastri was saying—I do not know if it is supported by the report, whether the report itself contains it—that sufficient material had not been given, papers were not made available to the Committee, the hon. Minister was asking: "Then, how did they make the report?" To the best of their ability. It is not right. If the Members of the Committee have expressed a feeling of frustration that many papers which ought to have been given to them were not given to them, you must thank them for having given a report in spite of the absence of those papers. The hon. Minister ought not to say: "How did they give a report?" It is not for Shri Prakash Vir Shastri to answer. It is for the hon. Minister to say.

I am really surprised why in a matter of such grave importance, where, unfortunately, even communal passions are likely to be roused, the Government, of its own accord, being a neutral party, did not bring it up to the House for a dispassionate discussion.

Dr. K. L. Shrimali: With all due respect to you, I really do not like to say anything in this matter, but I would like you to know that it was my intention.....

Mr. Speaker: What about these documents?

Dr. K. L. Shrimali: They are not with me.

Mr. Speaker: He must understand what I have said. Shri Prakash Vir Shastri said—I thought he read from the report—that the members of the Committee themselves had said that they did not receive sufficient assistance from the University authorities, that many important records were withheld, that witnesses were not forthcoming. I do not know if it finds a place in the report.

Shrimati Renu Chakravartty: It was not a blanket point like that. They have said it was so in certain matters. At last they have paid their compliment.

Dr. K. L. Shrimali: The difficulty is that Shri Prakash Vir Shastri has been speaking in Hindi, and I am afraid it has been probably difficult for you to fully understand what he was saying.

Mr. Speaker: But I understood his English.

Dr. K. L. Shrimali: As far as I have been able to understand, the Committee mentioned about certain data not being available. When he said the Committee had to face all these difficulties; that data was not available, I said, if it was lost, it was lost, if they did not have it, how could the university give it to them.

I have said in my speech very clearly that this report is not a compliment to the University and that the University must do everything quickly to set their house in order, that there are serious strictures against the administrative authorities of the University. I have made that very clear in my speech. I think the difficulty has arisen because he was speaking in Hindi.

Mr. Speaker: I have learnt sufficient Hindi, but not abusive speech so far.

"पानी देना मैंने नहीं सीखा है"

But the hon. Minister spoke in English in reply. He said: "How did they then prepare the report?" Shri Prakash Vir Shastri was complaining that some records, he did not say all the records, were not made available. Therefore, the hon. Minister must have said: "Those were not available, they have been lost", or "If they have not been produced, they are not so mattrial, the other material records have been there." It is not useful to say: "How then did they produce the report?" I did not like that attitude. I did not make that remark because I did not understand Hindi. I perfectly understand Hindi.

Dr. K. L. Shrimali: I shall be grateful if you will kindly allow me to explain one point. It was my intention to bring the motion before this House. But I wanted to bring it before this House after having examined this report fully. The executive committee did not consider it for a long time. They had to take some decision. After they have taken certain decisions, then Government should examine them. In the meanwhile, during the last session, Shri Prakash Vir Shastri brought this kind of a motion. While the Government were examining the position, this motion was brought in and had, therefore, no other alternative. I did not want to bring the motion before this House until the Government had made up their minds as to what should be done with regard to the recommendations. The university has accepted some and rejected the others. Government should make up their mind. So, I was not shirking my responsibility. I am fully aware of my responsibility.

About the other matter also, the Committee itself has mentioned more than once that the whole administrative machinery of this university is inefficient. They did not know how to maintain accounts and did not give proper figures. There are all kinds of things. The most inefficient administration that could be thought of is in the University. We cannot build up records. If they did not have the records, what is to be done? Some medical college was started, I believe, as early as 1935 or so. After that the full records are not available. What are we to do? We have now to think of the future. It is most unfortunate. I had said this in my speech clearly. I have not praised the University for its administrative ability. This report itself passed several strictures. It is very damaging to the administration of the University. The University should understand this matter. I think I have brought out the whole matter very clearly before the House and in view of the explanation which I have offered. I do hope that I would not be accused of being guilty of dereliction of duty in this matter.

Mr. Speaker: Is the amendment withdrawn?

Shri Bal Raj Madhok: I press it, Sir

Mr. Speaker: Then, I shall now put his amendment to the vote of the House. The question is:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"and feels that the enquiry was vitiated by the presence of the Vice-Chancellor of Aligarh University in the sitting of the Committee against the assurance to the contrary given by the Minister of Education on the floor of the House and by the atmosphere of terror created by certain interested parties as a result of which many intending witnesses did not appear before the Enquiry Committee."

The amendment was negatived.

Mr. Speaker: The main motion is a formal motion. It has been discussed. The question is:

"That this House takes note of the Report of the Aligarh Muslim University Enquiry Committee, laid on the Table of the House on the 21st April, 1961."

The motion was adopted.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTY-FIFTH REPORT

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): Sir, I beg to move:

"That this House agrees with the Eighty-fifth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 9th August, 1961."

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Eighty-fifth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 9th August, 1961."

The motion was adopted.

15·43 hrs.

RESOLUTION RE: INDIVIDUAL INCOME—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further discussion of the following Resolution moved by Shri Kalika Singh on the 28th April, 1961:

"This House is of opinion that in order to achieve the goal of socialistic pattern of society the individual incomes should be so regulated that the gap between the maximum and minimum income is reduced to the ratio of 10 to 1."

Out of 1½ hours allotted for discussion of this Resolution, 25 minutes have already been taken up. Shri D. C. Sharma.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Speaker, Sir, I have read the Resolution put forward by the hon. Member Shri Kalika Singh. I listened to his speech last time with rapt attention. I have again read through his speech as it has been reported in the proceedings of the Lok Sabha. On going through all these things, I have come to one conclusion that this Resolution is motivated by some very fine sentiments. This Resolution is steeped in a very idealistic spirit and it takes us to those goals which we all cherish and which we all have in view. This Resolution refers to those objectives which are the most cherished objectives of our Constitution and the Directive Principles of our Indian Constitution.

Now, Sir, first of all I want to put one question. Has anything like that been done in any country of the world which has socialism as its goal